CMYK

RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

वर्ष-10 अंक: 206 ता. 10 फरवरी 2022, गुरूवार , कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

संक्षिप्त खबरें

भाजपा विधायक के सामने ही भिड़े दो पक्ष, मारपीट के बाद थाने पहुंचा मामला

लखनऊ। यूपी के बांदा में भाजपा सदर विधायक और इस बार भी बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरे प्रकाश द्विवेदी के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गैर राजनीतिक संगठन साहू समाज की बैठक के दौरान ही प्रकाश द्विवेदी अपने लिए वोट मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान साहू समाज के लोग दो फाड़ हो गए और देखते ही देखते भिड़ंत हो गई। एक पक्ष ने प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। संगठन के दूसरे पक्ष ने अपने पदाधिकारी के लिखित बयान को ही झुठला दिया। कहा कि नितांत भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। बलंखडीनाका स्थित एक होटल में मंगलवार को उप्र साहू राठौर चेतना महासभा के पदाधिकारी और सदस्यों की बैठक रही। इसी दौरान सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी पहुंच गए। यहां विधायक का सम्मान भी हुआ। इसी सम्मान के दौरान नोकझोंक होने लगी। महासभा के रामशरण साहू, लवलेश साहू, राकेश साहू, रोहित साहू, दिलीप साहू सहित अनेक पदाधिकारियों ने लिखित बयान जारी कर आरोप लगाया कि प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरन अभद्रता, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी। बकायदा इसकी तहरीर शहर कोतवाली में भी दी। शाम को महासभा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने प्रेसनोट जारी किया। बताया कि बैठक के संबंध में तथ्यों को तोड़मरोडकर प्रस्तुत किया गया है, जोकि नितांत भ्रामक और तथ्यहीन है। उन्होंने जिला महासचिव के आरोपों को सिरे से खारिज किया।

हिजाब पर हंगामा जारी

बेंगलुरु में स्कूल-कॉलेजों के 200 मीटर के अंदर लोगों के जमा होने पर रोक, हाईकोर्ट ने केस बड़ी बेंच को भेजा

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले राज्य सरकार सभी स्कूल-कॉलेजों को तीन दिन तक बंद रखने का आदेश दे चुकी है। इधर, कर्नाटक हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सकता। बुधवार को यह केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में किसी की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार फैसला किया जाएगा। कर्नाटक के मांडया में मंगलवार को कॉलेज कैंपस में एक लड़की अल्ला-हू-अकबर के नारे लगाती नजर आई थी, तो छात्रों ने जय श्री राम के साथ जवाब दिया। अब इस मामले में सियासत गहरा गई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिकिनी हो या हिजाब, लड़कियों को कुछ भी पहनने का अधिकार है। वहीं, अक्टक्ट लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का समर्थन किया है। इससे पहले नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा था कि पहनावे को लेकर औरतों को शिक्षा से दूर करना सही नहीं है। आइए एक-एक करके जानते हैं । उत्तर प्रदेश के संभल में एक चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने कहा, 'मैं दुआ करता हूं कि कर्नाटक में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ने वाली बहनें कामयाब हों। कर्नाटक में संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं इखद सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं।' इस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने विवाद पर कहा, 'मंडया में स्टूडेंट अल्ला-हू-अकबर के नारे लगाने वाली लड़की का घेराव नहीं करना चाहते थे। जब वह नारे लगा रही थी, उस समय लड़की के आसपास कोई नहीं था। ऐसे में उसे किसने उकसाया? हम कॉलेज में 'अल्ला-हू-अकबर' और 'जय श्री राम' के नारों को बढ़ावा नहीं दे सकते।' कर्नाटक हिजाब विवाद पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। लालू ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वे महंगाई, गरीबी के बारे में नहीं बल्कि अयोध्या और वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा की हताशा से पता चलता है कि वे यूपी चुनाव हार जाएंगे। वे केवल दंगों और मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। 70 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था लेकिन अब बीजेपी के रूप में अंग्रेजों की वापसी हुई है... हम यूपी चुनाव में सपा का समर्थन करते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर मथुरा से भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा- स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं और वहां धार्मिक मामलों को नहीं लाया जाना चाहिए। हर स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप स्कूल के बाहर जो चाहें पहन सकते हैं। उधर, उत्तर प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' हैशटैग के साथ लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में मिला है।

क्या कोई बिकिनी पहनकर स्कूल जाता है: प्रियंका गांधी के ट्वीट पर ऋचा अनिरुद्ध ने घेरा

नई दिल्ली। हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 'बिकनी पहनकर' स्कूल जाने वाले बयान टीवी जर्नलिस्ट ऋचा अनिरुद्ध ने पलटवार किया है। ऋचा अनिरुद्ध ने प्रियंका के ट्वीट पर उनसे सवाल किया है कि क्या कोई बिकनी पहनकर स्कूल जाता है? इसके साथ-साथ ऋचा अनिरुद्ध ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की भी याद दिलाई। कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को कहा कि कोई महिला क्या पहनेगी यह तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'एक महिला का अधिकार है, वह बिकिनी पहनना चाहे, हिजाब पहनना चाहे, वह घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे या जींस पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना ही होनी चाहिए।' ऋचा अनिरुद्ध ने प्रियंका के ट्वीट का जवाब देते हुए पूछा कि एक लड़की बता दीजिए जो बिकनी, घूंघट या जींस में स्कूल जाती हैं! कृपया तथ्यों पर बात कीजिए। मुद्दा स्कूल यूनिफॉर्म का है और कुछ नहीं! भारतीय महिलाओं की पीढ़ियों ने एक प्रतिगामी पर्दा व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया है। आप इसे वापस चाहते हैं और भारत को ईरान बनाना चाहते हैं? इसके अलावा ऋचा अनिरुद्ध ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान याद दिलाया है। ऋचा अनिरुद्ध ने अशोक गहलोत के उस ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेयर किया है।

फिर बदले नजर आ रहे हैं नवजोत सिद्धू के तेवर

कहा- बिना 60 विधायकों के कैसे बनेगी सरकार

नई दिल्ली। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भले ही पंजाब में कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया हो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर उनके तेवर में बदलाव दिख रहा है। पंजाब की ओर से सीएम फेस की दौड़ में रहे राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह ने अपने एक ताजा बयान में कहा कि पंजाब के लोग निर्णय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चन्नी को कांग्रेस की ओर से सीएम फेस का ऐलान किया था, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके फैसले के साथ खड़े होने का दावा किया था। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में नवजोत सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब के लोग तय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या नहीं। अगर 60 विधायक नहीं जीत कर आए तो सीएम कैसे बनेगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि एक बाद हमेशा याद रखनी चाहिए कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है। सिद्धू ने आगे कहा कि यदि 60 विधायक हम जीतते हैं, तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी और की सरकार बनेगी। वहीं, सिद्धू ने कहा कि, ₹मेरा अगला कदम क्या होगा, ये लोग तय करेंगे। हम पंजाब का मॉडल रखेंगे। हम माफिया को खत्म करेंगे। माफिया का पैसा राज्य को जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के सीएम का चेहरा बनने की रेस में चन्नी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शामिल था। चन्नी को सीएम फेस बनाए जाने के बाद सिद्धू ने खुद को पंजाब का ₹आशिक₹ बताते हुए कहा था कि वह कभी किसी पद के लिए लालायित नहीं रहे और केवल राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की प्रशंसा की थी।

वोटिंग से पहले सीएम योगी का 'विजय सुनिश्चित' वाला ट्वीट, मोदी संग नई तस्वीर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नई तस्वीर पोस्ट करते हुए जीत की हुंकार भरी है। सीएम योगी ने इस पोस्ट में कहा है कि पीड़ित और शोषितों का दुख मिटाना है और राष्ट्रधर्म पर सीना ताने खड़े हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि जो लगातार श्रम करते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। योगी ने लिखा, "पीएम के संग नई तस्वीर दिखा बोले योगी आदित्यनाथ पीड़ित, शोषित, दु:खित बान्धवों के हमको हैं कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्रधर्म पर सीना ताने..., कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है॥" उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वे सभी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के हैं। मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का काम मंगलवार शाम 5 बजे बंद हो गया। पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में 2.27 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण का चुनाव जाट बहुल क्षेत्र में होगा। इस चरण में प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा।

वर्चुअल रैली में सीएम योगी बोले

आज रामपुर की गर्मी शांत हो चुकी है

रामपुर। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार को प्रस्तावित रामपुर दौरा टल गया लेकिन उन्होंने कार्यकताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज रामपुर की गर्मी शांत हो चुकी है। शायद इस बात से उन्होंने बिना नाम लिए सपा सांसद आजम खां पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार को रामपुर की बिलासपुर विधानसभा सीट में बिलासपुर नगर में सोमवार की बाजार स्थित रामलीला मैदान और पटवाई की बाजार के निकट रामलीला मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बुधवार को सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से रामपुर नहीं आ सके। इसके बाद दोपहर में उन्होंने सभा के निर्धारित समय के करीब ही कार्यकताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पांच साल में रामपुर में काफी परिवर्तन हुआ है। पांच साल पहले तक जिस उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, पर्व व त्योहार शांतिपूर्वक नहीं हो पाते थे, व्यापारी पलायन करता था, हर जगह भय-दहशत का माहौल था, आज पांच साल के बाद बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। हर जगह माहौल शांत है, कर्फ्यू लगने की जगह बढ़िया ढंग से कांवड़िया यात्रा निकल रही हैं। आज हर बेटी सुरिक्षत महसूस कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज रामपुर की गर्मी शांत हो चुकी है। इससे उनका इशारा शायद सपा सांसद आजम खां की ओर रहा हो। उन्होंने कहा कि पहले रामपुर में दलित, गरीब, बेटी कोई सुरक्षित नहीं था लेकिन, आज सुरक्षा की गारंटी है। पहले जमीनों पर कब्जे होते थे। इसके बाद उन्होंने रामपुर में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निशुल्क राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कर्जमाफी और किसान सम्मान निधि के तहत लाभ रहे रहे लाभार्थियों की संख्या को साझा किया। सीएम योगी ने कहा कि रामपुर में पांच साल में विकास ने तेजी पकड़ी है। सिर्फ रामपुर में ही बलदेव सिंह औलख के प्रयासों से करीब 24 सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं और ये विकास कार्य भाजपा सरकार बनने पर जारी रहेंगे। इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संबोधन के शुरूआत और अंत में कुछ मजाकिया अंदाज में भी दिखे। उन्होंने कहा कि पता नहीं बलदेव सिंह औलख क्या करते हैं कि मैं रामपुर नहीं आ पाता। पांच साल पहले भी मैं रामपुर नहीं आ सका और आज फिर मौसम खराब करवा दिया, जिस कारण मैं रामपुर नहीं आ सका।

सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे जेल में बंद मुख्तार अंसारी, राजभर की पार्टी ने दिया टिकट

मऊ। सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी एक बार फिर चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सपा गठबंधन में शामिल ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया है। मुख्तार का नामांकन फार्म भरने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई है। कोर्ट गुरुवार को मामले पर सुनवाई करेगी। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने लाइव हिन्दुस्तान से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि कोरोना के देखते हुए इस समय जेल में मुलाकात पर रोक लगी हुई है। इसी को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में अर्जी दी गई है। अर्जी में कहा गया है कि नामांकन फार्म भरने के लिए मुख्तार से मिलना जरूरी है। ऐसे में उनके अधिवक्ता, प्रस्तावकों, नोटरी अधिवक्ता और फोटोग्राफरों की मुलाकात की अनुमति मांगी गई है। मंगलवार को दायर की गई अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन हड़ताल के कारण अब गुरुवार को होगी। सुभासपा की तरफ से अभी टिकट की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के सवाल पर अधिवक्ता ने कहा कि पार्टी के महासचिव और ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की तरफ से उन्हें मुख्तार अंसारी के लिए अधिकृत पत्र व अन्य जरूरी दस्तावेज दिये गए हैं।

प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ किया जाएगा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। उन्होंने प्रदेश में दो लाख खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का वादा किया। पुरानी पेंशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जनता की आकांक्षाओं को शामिल किया है। इसके लिए हमारी घोषणा पत्र टीम के सदस्य अलग-अलग जिलों में गए और लोगों से बात की और जैसा जनता में कहा हमने उन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अलग-अलग पार्टियों का घोषणा पत्र देखने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही भाषा पर कहा कि कोई कहता है, गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे। अगर निकालना है तो भर्ती निकालिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस का तीसरा घोषणा पत्र है। इसके पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और अब अंतिम घोषणा पत्र 'उन्नति विधान' जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम अब तक दो घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं जिसमें से पहला महिलाओं के लिए और दूसरा युवाओं के लिए था।

मुलायम के कहने पर अखिलेश संग आए शिवपाल के मन में 'ठगे' रह जाने का है दर्द, चाचा-भतीजे के रिश्ते में फिर खटास

लखनऊ।। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शिकस्त देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने को बेकरार समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिश्तों में आई खटास को दूर करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) को गठबंधन में शामिल तो कर लिया है मगर सत्ता की खातिर दोनों के बीच हुआ यह समझौता कितना टिकाऊ साबित होगा, इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इटावा में अपनी परंपरागत सीट जसवंतनगर से शिवपाल सपा के चुनाव चिह्न साइकिल के साथ चुनाव मैदान पर हैं, मगर उम्मीद से कोसों दूर उनकी पार्टी को गठबंधन में सिर्फ इसी सीट की हिस्सेदारी से संतुष्ट होना पड़ा है जबकि उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में थे, नतीजन प्रसपा के कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ कर अन्य दलों का रुख कर चुके हैं। शिवपाल के मन की यह टीस रह रह कर उनके बयानों से झलकती रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान एक ढाबे में रुके शिवपाल का दर्द उनकी जुबान से बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि वह अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव (नेता जी) का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के कहने पर सपा गठबंधन का हिस्सा बने थे। उन्होंने कहा, "नेताजी कहते थे कि कम से कम 100 सीटें लेना, फिर बोले कम से कम से 200 सीटें लेना लेकिन मैंने तो केवल 100 ही मांगी थी मगर उन्होंने (अखिलेश) ने कहा कि कुछ कम कर दो, तो पहले 65, फिर 45 और फिर 35 कर दी, फिर बोले यह भी ज्यादा है फिर मैंने कहा कि सर्वे करा लो, जितने भी हमारे जीतने वाले लोग हों, उन्हीं को टिकट दे दो । हम तो समझते थे कि कम से कम 20 या 25 लोगो को टिकट दे देंगे।" उन्होंने कहा, "हमारी सूची में सभी जीतने वाले लोग थे। अगर हमारी मान ली होती तो इटावा सदर सीट पर कितना बढ़िया चुनाव होता। एकतरफा चुनाव होता लेकिन जब सूची निकली, तब केवल एक सीट मिली इसलिए हम चाहते है कि सबसे बड़ी जीत इस सीट पर उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए।" शिवपाल ने कहा, "अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए हमने अपनी पार्टी का बलिदान कर दिया, जबकि एक वर्ष पूर्व हमने सौ टिकटों की घोषणा कर दी थी, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भी निकाली। जनता का अपार प्यार मुझे मिला। इसलिए अब हमारी अपील है कि जसवंतनगर विधानसभा से इतनी बड़ी जीत करवा देना, जिससे हमारा बलिदान बेकार न जाए।

सार समाचार

पुराने पेंशन के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालना होगा : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सरकारी कर्मचारियों का पुराना पेंशन बहाल करने के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की वकालत की है। प्रियंका ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में पुराना पेंशन बहाल करने की कर्मचारियों की पुरानी मांग पर पार्टी का रूख पूछे जाने पर कहा, पुराने पेंशन पर हमने बहुत चर्चा की है। हमें लगता है कि इसपर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशन में अपना योगदान बढ़ाना चाहिए। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी अरसे से पुराना पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में पुराना पेंशन बहाल करने का वादा कर प्रदेश के करीब 13 लाख सरकारी कर्मियों को लुभाने की कोशिश की है। 2004 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके नई योजना लागू की थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।

हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा केस

बैंगलोर। कर्नाटक हिजाब विवाद में आज लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दलील दी गई है ये मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। जिसके बाद कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए भेजा। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। मामले में सभी की नजरें बैंगलोर हाईकोर्ट के फैसले पर थी। हाईकोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की थी जज ने ये साफ कर दिया था कि मामला गंभीर है। सरकारी पक्ष की तरफ से ये अपील की गई थी कि पूरी बहस एडवोकेट हेड़गे का वो सुना जा चुका है। उसके साथ राज्य सरकार की जिरह बाकी है। वो पूरी होने के बाद फैसला दें। सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, जिसे बड़ी बेंच के पास मामला भेजा जाए। संवैधानिक के साथ ही एक जजमेंट को रेफर करते हुए कहा गया कि पर्सनल लॉ और संवैधानिक कानून में ज्यादा कुछ अतंर नहीं बचा है। यूनिफॉर्म जो पहनने का नियम बनाया गया है उसे ही कायम रखना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि हिजाब पहनना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम में नहीं आता है। छात्राओं की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा उडुपी में ही हुई है और उन्होंने ये चीजें पहले देखी हैं। राज्य सरकार के रुख ने इसे अपने लिए और खराब कर दिया है। राज्य का कहना है कि उसने कुछ भी प्रतिबंधित नहीं किया है। यह बेकार है।

महिला सुरक्षा भाजपा की प्राथमिकता, 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाएंगे

लखनऊ । उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार अपने दांव-पेंच लगाने में जुटे हुए हैं इस बीच केंद्रीय मंत्री और उत्तरप्रदेश में भाजपा के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि महिला सुरक्षा भाजपा की प्राथमिकता है,उत्तरप्रदेश में लगातार नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकारण दूसरे दलों की बहने भी अब भाजपा में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की नौकरी भी दोगुनी की जाएगी। अनुराग ने कहा कि 1000 करोड़ की लागत से महिला शौचालय बनवाए जाएंगे। इस योजना को हम पिंक योजना के नाम से आगे चलाएंगे। ठाकुर ने कहा कि करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, अब होली और दीपावली पर दो रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ़्त में दिए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए गुंडई, मारपीट को बढ़ावा देती हों, जो पलायन कराते हो,वहां अब उत्तर प्रदेश में दूसरे दंगाई से मिलने आकर यहां भी बंगाल जैसे हालात बनाना चाहते हैं।

हेल्थ, एफडीए और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में फर्जी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देने वालों को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ । स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के निदेर्शानुसार स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में फर्जी कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट्स देने वालों के गिरोह के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम ने मौके से लैपटॉप व अन्य फर्जी दस्तावेजों को भी जब्त किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को फर्जी कोविड रिपोर्ट्स बनाने वाले रैकेट के बारे में निरंतर मिल रही सूचनाओं पर कार्यवाही करने के आदेश की अनुपालना में गत दिवस को खाद्य एवम औषधी प्रशासन, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 में गुड लाइफ हेल्थ केयर सेंटर पर छापा मारा और इस टीम में जिला औषधी नियंत्रण अधिकारी श्री मनदीप मान, डॉ नमन, डॉ रामप्रकाश राय, उप-निरीक्षक सतेंदर व उप-निरीक्षक रणधीर शामिल थे। उन्होंने बताया कि टीम ने गुड लाइफ हेल्थ केयर सेंटर, डीएलएफ-3, जोकि एसआरएल डायग्नोस्टिक का कलेक्शन सेंटर है, पर एक छदम (डेकोय) ग्राहक भेजकर लैब के मैनेजर अनुज शर्मा व कर्मचारी संजीव को 2000 रुपये में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देने पर मोके से गिरफ्तार किया व दोनों दोषिओ के विरुद्ध थाना डीएलएफ फेज-3 में एफआईआर दर्ज करवा दी गयी है। प्रवक्ता ने बताया कि मौके से कई फर्जी कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स व सरकार द्वारा निर्धारित टेस्ट रेट से ज्यादा रेट चार्ज करने की रसीदे व लैपटॉप सहित अन्य रिकॉर्ड बरामद हुआ है, जिसको टीम ने अपने कब्जे में ले लिया।

10 फरवरी को श्रीनगर और 11 फरवरी को अल्मोड़ा में रैली करने वाले पीएम मोदी

देहरादून । उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख भाजपा के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को श्रीनगर में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी साझा कर कहा कि वह प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिए 10 फरवरी को श्रीनगर पंहुच रहे हैं।उन्होंने कहा कि आज वह सबसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुडे.हैं लेकिन इस चुनाव में वह पहली बार 10 फरवरी को श्रीनगर में उनसे रूबरू होने वाला हूं। मोदी ने कहा, इस दौरान मैं आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। उत्तराखंडवासियों से आशीर्वाद लेने का और देवभूमि को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट पर पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच सीधा मुकाबला है। कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से हो रहे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री उत्तराखंड में कई जनसभाओं को वर्चुअल रूप से संबोधित कर चुके हैं। उधर, प्रदेश भाजपा महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को अल्मोड़ा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तय है।

पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती, राहुल के नाना पंडित नेहरू के दिनों की हैं: राजनाथ

देहरादून (एजेंसी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान के मित्र बनने के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार कर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती नेहरू के दिनों की है, यह कांग्रेस सरकारों के समय में बढ़ी थी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए सिंह ने कहा कि टिप्पणी से पता चलता है कि कांग्रेस नेता ने स्वतंत्र भारत का इतिहास भी नहीं पढ़ा है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल में संसद में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसकी गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद में गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान आपस में दोस्त हो चुके हैं।

शायद उन्होंने आजाद भारत का इतिहास भी कभी पढ़ा नहीं है। प्राचीन इतिहास,तब पढ़ा ही नहीं होगा। मध्ययुगीन इतिहास भी नहीं पढ़ा होगा। सिंह ने कहा, पाकिस्तान का शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा था और जिस समय पाकिस्तान ने उस चीन के हवाले किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब चीन ने कराकोरम राजमार्ग बनाया,तब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर 2013 में जिस समय बनना प्रारंभ हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया। सिंह ने गलवान घाटी में हुई झड़प पर टिप्पणी को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'आस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने हाल में पाया कि गलवान संघर्ष में कम से कम 38-50 चीनी सैनिक मारे गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि लोगों को कांग्रेस जैसे दलों को माफ नहीं करना चाहिए।

अन्ना हजारे महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ 14 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे

पुणे (महाराष्ट्र)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बुधवार को कहा कि वह सुपरमार्केट और किराना दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली महाराष्ट्र सरकार की नीति के विरोध में 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हजारे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। ठाकरे को लिखे अपने पत्र में हजारे ने कहा कि राज्य के लोगों ने मांग की है कि सुपरमार्केट और आस-पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली नीति को तुरंत वापस लिया जाए। हजारे (84) ने एक बयान में कहा कि वह 14 फरवरी को अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हजारे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए दो पत्र लिखे थे, जिसमें उनसे निर्णय वापस लेने का आग्रह किया गया था, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला। अपने पिछले पत्रों में हजारे ने कहा था कि सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगा।

सपा के बढ़ती लहर को देखकर भारी मात्रा में कांग्रेस भाजप छोड़कर लोग सपा के साथ जुड़े

सूरत भूमि, सूरत।

शहर के डिंडोली विस्तार में निवास करने वाले आनंद मिश्रा वर्षों से कांग्रेस की राजनीति करते आए थे, परंतु गुजरात में कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ को देखकर भाजप का हाथ थाम लिए थे और सूरत शहर में भाजपा के अंदर सदस्यता लेकर जनता की सेवा का कार्य कर रहे थे। परंतु कोरोना काल में लोगों को जीने का नया तरीका मिला हम लोगों को एहसास हो गया की इस धरती पर अपना कोई नहीं है क्योंकि जब कोरोना महामारी जैसी बीमारी का भारत में पदार्पण हुआ तो जबाबदार नेताओं ने और मीडिया द्वारा फैलाई गई खबर के आधार पर जनता में घबराहट का माहौल पैदा हो गया और महाराष्ट्र गुजरात तथा दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले मजदूर श्रमिक वर्ग के लोग अपने वतन के लिए पलायन करने लगे जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इस जमाने में भी लोगों को मौत से डर नहीं है लेकिन अपने वतन से प्रेम है अगर मरे भी तो अपने वतन में इसलिए लोग पैदल साइकल मोटरसाइकिल ट्रक बस जैसे साधनों से यात्रा करने लगे इस स्थिति को देखकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगाज किया कि श्रमिकों को घर भेजा जाए उनका खर्च में वाहन करूंगी। इस बात से भी कुर्सी के लोगों नेता सियासत करने लगे और गुजरात से उत्तर प्रदेश बिहार के लिए प्रस्थान करने वाली ट्रेनें कांग्रेसी नेताओं को नहीं दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता का भोग कर रहे थे वे लोग जनता का जेब खाली कर अपनी तिजोरी भरने के लिए ट्रेन का टिकट खरीद कर 2 गुना 3 गुना 4 गुना भाव से बेचने लगे,ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रस्थान करने वाले मजदूर पैसे ना होने पर अपने घर में रखे जेवरात बेच कर टिकट खरीदें और अपने गांव गए जहां गांव के लोग भी उन्हें अपना समझ कर प्रेम से नहीं अपनाए बल्कि कोरोना के डर से काफी दूर रख कर उन्हें कोरोना मुक्त किया गया। ऐसी स्थित में लोगों के परिवार जन का स्नेह और प्रेम उनसे है

या नहीं इसकी अस्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई उसी भीड़ में सूरत से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करने वाले नेता आनंद मिश्रा आज उत्तर प्रदेश में सपा प्रदेश प्रमुख अवधेश यादव के नेतृत्व में गोरखपुर छावनी में जाकर सपा का दामन थाम लिया और प्रचार-प्रसार में जुट गए। यह जानकारी उन्होंने खुद हमारे संवाददाता को दी और बताया कि जिस तरह 2014 में मोदी लहर फैली थी उसी तरह आज 2022 में अखिलेश लहर फैली हुई है इसलिए मैंने सपा का दामन थाम लिया और पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बनाने का प्रयास कर रहा हूं।

केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा ने किया प्रदर्शन, किसानों से किये वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा किसानों की मांगें कथित रूप से पूरी नहीं किये जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले किसानों से कई बड़े वादे किये थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा कि 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने भी इसमें भाग लिया। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों को सिंचाई के वास्ते मुफ्त बिजली का वादा किया था लेकिन उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिली। उन्होंने कहा, 'एक तरह से, सरकार किसानों को रोक रही है। केजरीवाल सरकार किसानों को अपने खेतों में ट्यूबवेल नहीं लगाने देती है। यदि वे किसी तरह ट्यूबवेल लगवा लेते हैं तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। किसानों को इस तरह की नाइंसाफी और अपराध का शिकार बनाया जाता है।' भाजपा नेता ने कहा, 'उन्होंने (केजरीवाल ने) लाल डोरा बढ़ाने का फैसला किया था लेकिन अब तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया।' उन्होंने दावा किया कि जिन किसानों की मौत हो गय , उनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व विभाग के रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं।

ईडी चला रही क्रिमिनल सिंडिकेट, सरकार गिराने के लिए बनाया जा रहा दवाब, संजय राउत ने उपराष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया अनुरोध

मुंबई (एजेंसी)

शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के जरिये ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि उन पर ठाकरे सरकार को गिरवाने के लिए दवाब डाला जा रहा है। संजय राउत का कहना है कि मना करने पर उन्हें ईडी के जरिये फंसाने की कोशिश हो रही थी। नायडू के अलावा संजय राउत ने विपक्ष के नेताओं को भी चिट्ठी लिखी है।

संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल ब्कलैकमेल करने के लिए कर रही है। संजय राउत ने कहा कि एक क्रिमिनल सिंडिकेट ईडी चला रही है। मैं सबूत के साथ सामने आ जाऊंगा। मैं अभी गोवा जा रहा हूं, जल्द ही मुंबई जाऊंगा और ईडी कार्यालय के सामने हजारों लोगों के साथ मैं प्रेस कॉनफ्रेंस करूंगा और पूरे देश में क्या चल रहा है मैं बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि इमरजेंसी के बारे में तो प्रधानमंत्री रो रहे थे। आक्रोश कर रहे थे। इन सब को लेकर मैंने वैंकैया जी को लेटर लिखा है।

संजय राउत ने उ नायडू को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि उनसे 'कुछ लोगों' ने संपर्क कर महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को गिराने में सहायता करने के लिए कहा था ताकि राज्य को मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर किया जा सके। नायडू को लिखे पत्र में राउत ने कहा कि अपनी पुरानी सहयोगी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में राकांपा और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तब से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां शिवसेना के नेताओं को सुनियोजित रूप से निशाना बना रही हैं। राउत ने नायडू से 'सत्ता के दुरुपयोग' और राज्यसभा सदस्यों को कथित तौर पर परेशान किए जाने के विषय पर ध्यान देने का अनुरोध किया और कहा कि उपराष्ट्रपति को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।

संसदीय समिति ने मनरेगा में निधि जारी होने में विलंब सहित अन्य पहलुओं की निगरानी की सिफारिश की

नयी दिल्ली (एजेंसी)

संसद की एक समिति ने ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक स्तर पर मनरेगा के पहलुओं की निगरानी करने की सिफारिश की है ताकि समय पर निधि जारी करने के लिए सभी पूर्व आवश्यकताएं और औपचारिकताएं पूरी हो जाये।

समिति ने बताया कि मनरेगा के पहलुओं की निगरानी करने की सिफारिश इसलिए भी की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत पर योजनाएं अधूरी न रह जाए या उसमें विलंब न हो। लोकसभा में मंगलवार को पेश 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का समालोचनात्मक मूल्यांकन' विषय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना की वित्तपोषण पद्धति स्पष्ट रुप से रेखांकित करती है कि केंद्र सरकार कुशल और अकुशल श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना की सामग्री लागत की तीन चौथाई तक वहन करेगी जबकि राज्य सरकार कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना सामग्री लागत का एक चौथाई खर्च वहन करेगी। इसमें कहा गया है, 'निधियों के स्रोत और उसके अनुमानित प्रवाह के स्पष्ट सीमांकन के बावजूद उक्त घटकों को जारी करने में विलंब होता रहा है। यह विलंब अंततः मनरेगा के कार्यों को पूरा करने में देरी का कारण बनता है जिसके कारण मनरेगा के तहत शुरू की गई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती और अक्सर लंबे समय तक लटकी रह जाती है।' रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा के तहत टिकाऊ परिसंपत्ति के निर्माण की पूरी कवायद इन्हीं कारणों से विफल हो जाती है। विभाग से जब इस पहलू के बारे में पूछा गया तो निधि की अगली किस्तों को जारी करने के लिए दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पुराना होना जैसे कारण बताए गए। इसके अनुसार समिति को लगभग अधिकांश अवसरों पर एक की तरह का बहाना सुनने को मिलता है जिससे दोषारोपण चलता रहता है लेकिन निवारण नहीं होता है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक स्तर पर इन पहलुओं की निगरानी करने की सिफारिश करती है ताकि समय पर निधि जारी करने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाए और निधि जारी नहीं होने के कारण योजना अधूरी न रह जाएं या उसमें विलंब न हो। इसमें कहा गया है कि, 'समिति यह देखकर चकित और स्तब्ध है कि मनरेगा 2005 की धारा 7 (1) के माध्यम से और निर्देशित बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान का घोर उल्लंघन किया जा रहा है।' रिपोर्ट के अनुसार, इसमें परिकल्पना की गई है यदि योजना के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा जो वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगा तथा वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से भी कम नहीं होगा। इसके अनुसार, 'कानून में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है लेकिन इसके विपरीत मंत्रालय के आंकड़े निराशाजनक तस्वीर को दशार्ते है।

राज्यसभा में उठी पाक जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को वापसी और अफगान बटालियन बनाने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)

राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय मछुआरों की सुरक्षित स्वदेश वापसी, गोरखा बटालियन की तरह अफगान बटालियन बनाने, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने और संसद में सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का तैल चित्र लगाने की मांग की।

इसके साथ ही सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा छात्रवृत्तियों में लगातार की जा रही कटौतियों, केरल में वन्य जीवों द्वारा नागरिकों के जान व माल को नुकसान पहुंचाने और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा नदी की स्वच्छता और निर्मलता में कोई सुधार नहीं होने का दावा करते हुए इन विषयों पर चिंता भी जताई। शून्यकाल में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना द्वारा उठाकर ले जाने और वहां की जेलों में बंद करने का मामला उठाया और केंद्र सरकार से उन्हें वापस भारत लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा करीब 643 भारतीय मछुआरे इस समय पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। गोहिल ने भारत सरकार से इन मछुआरों को सुरक्षित वापस वापस लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सभी प्रकार के प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा चाहे आंखें लाल ही क्यों न करनी पड़ी, मछुआरों की सलामती के लिए सरकार प्राथमिकता से पहल करे। गोहिल ने कहा पिछले एक सप्ताह में तीन अलग-अलग घटनाओं में पाकिस्तानी समुद्री सेना ने तीन नौकों और 27 मछुआरों को अपनी गिरफ्त में लिया है जबकि एक दिन पहले ही वह 10 नौकाओं और 60 मछुआरों को लेकर गए हैं। द्रविड़ मुनेत्र कणगम (द्रमुक) के पी विल्सन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा 1963 के बाद से न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि 90 से अधिक उम्र में भी कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश विभिन्न पदों पर प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा संसद की विभिन्न समितियां भी उम्र सीमा बढ़ाए जाने की सिफारिश कर रही है लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा ऐसे में इन समितियों का क्या उपयोग है, जब सरकार समितियों की सिफारिशों पर विचार ही नहीं कर रही है जबकि इन पर लाखों रूपए खर्च होते हैं और सदस्य भी अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं। उन्होंने संसदीय समिति के नियमों में बदलाव कर इसकी सिफारिशों को सरकार के लिए बाध्यकारी किए जाने की मांग की और कहा कि यह इस बदलाव का उपयुक्त समय है। राष्ट्रीय जनता दल के केडी सिंह ने भारतीय सेना में गोरखा बटालियन की तरह अफगान बटालियन बनाने और उन्हें पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कश्मीर में तैनात करने की मांग संबंधी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में अफगानी छात्रों ने भारत में वीजा के लिए आवेदन किया है लेकिन सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा अफगानी भारत समर्थक होते हैं, हम उन्हें वीजा दे सकते हैं, ऐसा करके हम एक अफगानी बटालियन तैयार कर सकते हैं। गोरखा और अन्य बटालियनों की तरह और कश्मीर में तैनात कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान की हरकतों का करारा जवाब दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सीमा द्विवेदी ने सुर साम्रज्ञी लता मंगेशकर की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा देते हुए सरकार से उनका तैल चित्र संसद भवन में लगाने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वी शिवादासन ने छात्रों को मिलने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों में यूजीसी द्वारा की जा रही लगातार कटौतियों का मुद्दा उठाया और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की।

सार समाचार

एक गांव जहां मर्दों के प्रवेश पर है 30 साल से पाबंदी, फिर भी महिलाएं होती हैं गर्भवती!

अफ्रीका में एक ऐसा गांव है जहां 30 साल से किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित है लेकिन फिर भी महिलाएं तेजी से गर्भवती हो रही हैं। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह काफी अजीब है कि अफ्रीका के इस गांव में कोई भी पुरूष 30 साल से नहीं आया है लेकिन उसके बावजूद इस गांव की महिलाएं गर्भवती हो रही है। बता दें कि, इस गांव का नाम उमोजा है। यह गांव दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल में बसा हुआ है जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं। इस गांव में करीब 250 महिलाएं रहती हैं। इस गांव का निर्माण साल 1990 में 15 महिलाओं ने किया था। इन 15 महिलाओं का कथित तौर पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बलात्कार और शारीरिक शोषण किया गया था। जिसके बाद इन महिलाओं के मन में पुरुषों के प्रति नफरत बढ़ने लगी और विरोध में आकर इन महिलाओं ने घने जंगल में एक गांव बनाने का निर्णय लिया। इस गांव में शोषित महिलाओं को शरण दिया जाता है। साथ ही पुरुषों का इस गांव में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

कैसे हो रही महिलाएं गर्भवती

जिस गांव में पुरुषों का किसी भी तरह से प्रवेश वर्जित है, वहां आखिर महिलाएं गर्भवती कैसे हो रही हैं? बता दें कि, पुरुषों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है लेकिन फिर भी कई पुरुष रात में गांव में घुस जाते हैं। महिलाएं अपनी पसंद के पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं जिससे वह गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद यह महिलाएं उन पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं बनाती है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनकी देखभाल खुद करती हैं।

तालिबान में मरीज तेजी से हो रहे हिंसक, कच्चा चबा रहे इंसान का मांस

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि, अफगानिस्तान में ड्रग रिहैब सेंटर्स में मरीज मानव मांस खा रहे है। डेनमार्क के एक पत्रकार ने हाल ही में ऐसा दावा किया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेनिश पत्रकार ने पिछले महीने एक रिहैब सेंटर से रिहा हुए एक शख्स से बात की थी। उस व्यक्ति ने दावा किया कि तालिबान द्वारा संचालित पुनर्वसन केंद्र के अंदर का माहौल भयानक था। मरीजों को ठीक से खाने की अनुमति नहीं है। उन्हें ज्यादातर दिन भूखे रहना पड़ता है। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कई लोग उचित इलाज के बिना मर रहे हैं। अब्दुल नाम के मरीज ने दावा किया कि रिहैब सेंटर में हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि, बिना भोजन के मरीज तेजी से हिंसक होते जा रहे हैं। अब्दुल का दावा है कि हाल ही में कुछ लोगों ने एक शख्स की हत्या कर उसका मांस खाया है। मरीजों ने बीच के एक पार्क में एक बिल्ली को पकड़ कर उसका कच्चा मांस भी खा लिया। काबुल में ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रमुख सीजर गुड्स ने कहा कि तालिबान ने अफीम का उत्पादन बढ़ाया है। जिसके कारण दवाओं की कीमत में और कमी आई है।संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में बढ़ते अवैध अफीम और हेरोइन की खेती से अधिक से अधिक लोग नशे के आदी हो रहे हैं। साल 2017 में अफगानिस्तान ने दुनिया में अकेले अफीम की 80 फीसदी से अधिक आपूर्ति की थी।

ईयू ने आतंकवाद-निरोधक कानून में बदलाव के श्रीलंका के कदम का स्वागत किया

कोलंबो। यूरोपीय संघ (ईयू) ने आतंकवाद-निरोधी कानून में संशोधन करने के श्रीलंका के कदम का स्वागत किया है लेकिन साथ ही कहा है कि श्रीलंका सरकार की अधिसूचना में कई 'अहम तत्वों' को शामिल नहीं किया गया है। ईयू ने कोलंबो से बिना आरोप तय किए कानून के तहत हिरासत में रखे गए लोगों को जमानत पर रिहा करने के लिए अधिक व्यावहारिक और प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह भी किया है। यूरोपीय संघ श्रीलंका पर उसके विवादित आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) में बदलाव करने का दबाव बना रहा है, जो व्यक्ति को बिना आरोप तय किए 90 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है और जिसमें हिरासत अवधि को बढ़ाने के प्रावधान भी मौजूद हैं। श्रीलंका सरकार ने 27 जनवरी को एक गजट अधिसूचना जारी कर पीटीए में संशोधन की घोषणा की थी। तब अधिकारियों ने इसे पीटीए को अंतरराष्ट्रीय मानक के आतंकवाद निरोधक कानूनों के अनुरूप बनाने की कवायद करार दिया था। ब्रसेल्स में मंगलवार को ईयू-श्रीलंका के संयुक्त आयोग की 24वीं बैठक के समापन के बाद मीडिया के लिए जारी साझा बयान में कहा गया है, 'यूरोपीय संघ आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) में संशोधन के श्रीलंका सरकार के फैसले का स्वागत करता है। लेकिन, ईयू ने गौर किया है कि संशोधित विधेयक में कई अहम तत्वों को शामिल नहीं किया गया है।' बयान के मुताबिक, ह्ययूरोपीय संघ श्रीलंका से पीटीए के इस्तेमाल में कमी जारी रखने का अनुरोध करता है। वह कोलंबो से बिना आरोप तय किए पीटीए के तहत हिरासत में रखे गए लोगों को जमानत पर रिहा करने के लिए अधिक व्यावहारिक और प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह करता है।

क्रिप्टोकरेंसी के रूप में 3.60 अरब डॉलर अवैध धन जब्त, हैक करने का लगा आरोप

वाशिंगटन। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 3 .60 अरब डॉलर से अधिक अवैध धन जब्त किया है और इस संबंध में न्यूयार्क के एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। दंपति पर आरोप है कि उन्होंने 2016 में डिजिटल माध्यम से हुए मुद्रा विनिमय प्रणाली को हैक कर चुराए गए अरबों डॉलर के शोधन की साजिश रची। संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि जब्त किया गया धन 'बिटफिनेक्स' को हैक करने के मामले से जुड़ा है जो कि डिजिटल माध्यम से मुद्रा विनिमय की एक प्रणाली है और छह साल पहले इसमें हैकरों ने सेंध लगाई थी। अमेरिका और रूस की नागरिकता रखने वाले 34 वर्षीय इल्या 'डच' लिचेंस्टाइन और उसकी पत्नी हेदर मोर्गन (31) को मंगलवार को मैनहैटन में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने जटिल तकनीक का इस्तेमाल कर चोरी की गई 'क्रिप्टोकरेंसी' का शोधन करने और धन के लेनदेन को छिपाने की साजिश रची। न्याय मंत्रालय की ओर से जारी एक वीडियो बयान में उप महान्यायवादी लीजा मोनाको ने कहा, 'अपराधियों को स्पष्ट संदेश है कि क्रिप्टोकरेंसी चोरी कर वे बच नहीं सकते। हम अवैध धन का पता लगाते रहेंगे, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो।

पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले में हिंदू शिक्षक को उम्रकैद की सजा

कराची। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को ईशनिंदा के मामले में एक हिंदू शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई। सिंध के घोटकी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुर्तजा द्वारा शिक्षक नौतन लाल पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया। अदालत ने 2019 से जेल में बंद लाल को दोषी ठहराया। पिछले दो साल में लाल की जमानत अर्जी दो बार खारिज हुई। लाल को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था।

पेरिस में नाइस कार्निवाल के लिए तैयारी करते हुए व्यक्त।

एवरेस्ट पर स्थित दो हजार साल पुराना ग्लेशियर इस सदी के मध्य तक गायब हो सकता है: अध्ययन

काठमांडू। नेपाल में अनुसंधानकताओं ने मंगलवार को चेतावनी दी कि माउंट एवरेस्ट पर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर इस शताब्दी के मध्य तक गायब हो सकता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी पर स्थित दो हजार साल पुराना हिमखंड तेजी से पिघल रहा है। यहां स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (आईसीआईएमओडी) ने हाल में प्रकाशित एक शोधपत्र के हवाले से कहा कि एवेरेस्ट पर 1990 के दशक से लगातार

बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल रही है। आईसीआईएमओडी ने कहा कि एवरेस्ट पर किये गए सबसे व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन 'द एवरेस्ट एक्सपेडिशन' के तहत ग्लेशियरों पर गहन अनुसंधान किया। 'नेचर पोर्टफोलियो' में हाल में प्रकाशित एक आलेख में कहा गया कि एवरेस्ट पर बर्फ बेहद तेजी से पिघल रही है। इस अनुसंधान में आठ देशों से वैज्ञानिकों ने भाग लिया जिसमें से 17 नेपाल के हैं। अध्ययन में शामिल तीन सह लेखक आईसीआईएमओडी से सम्बद्ध हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 8,020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साउथ कोल ग्लेशियर लगभग दो मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहा है। अनुसंधानकताओं ने 'रेडियो कार्बन डेटिंग' के माध्यम से पता लगाया है कि ग्लेशियर दो हजार साल पुराना है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह ग्लेशियर इस सदी के मध्य तक पिघल जाएगा। अनुसंधान में कहा गया है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है।

जो बाइडन ने दी रूस को चेतावनी, कहा-अगर यूक्रेन पर हमला किया तो गैस पाइपलाइन परियोजना को कर देंगे खत्म

न्यूयार्क (एजेंसी)

यूक्रेन संकट के चलते अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर रूस चेतावनी दी। सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस को सख्त लहजे में कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस से गैस सप्लाई के लिए बनाई गई नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बनने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनकी ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को कैसे रोका जाएगा। आपको बता दें इससे पहले जिस पाइपलाइन से यह सप्लाई की जाती थी वह यूक्रेन से होकर गुजरती थी। रूस के द्वारा हर वर्ष यूक्रेन को इसके लिए करोड़ों रुपए की अदायगी की जाती थी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 यूक्रेन की सीमा से अलग समुद्र से होकर गुजरती है। इसकी वजह से यूक्रेन को हर साल दी जाने वाली रकम का बोझ नहीं पड़ेगा। इस पाइप लाइन से गैस की सप्लाई जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे हिस्से में भी होगी। आपकी जानकारी के

लिए यहां यह भी बता दें कि जर्मनी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस के गैस और तेल का बड़ा खरीदार है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलज (ड'ा रुँड्ड'९) के साथ एक जॉइंट संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा की रूस के यूक्रेन के ऊपर हमला करने की सूरत में गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसे हम खत्म कर देंगे। जब बाइडन से सवाल पूछा गया कि इसे किस तरह खत्म किया जाएगा तो, उन्होंने जवाब में बस इतना ही कहा कि हम इसे करने में सक्षम होंगे। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन में संभावित रूसी सैन्य हमले के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

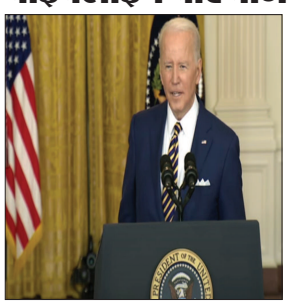

अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि अमेरिका और जर्मनी एक ही तरह से सोचते हैं। दोनों ही रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें जर्मन चांसलर बीते दिनों मॉस्को के दौरे पर गए थे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका इस बारे में नहीं जानता है कि इस दौरान नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर क्या बातचीत हुई।

क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2

ये रूस के एक महत्वकांक्षी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पश्चिमी रूस से लेकर पूर्वोत्तर जर्मनी तक बिछाई गई है। इस गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 1275 किलोमीटर है। रूस की एक सरकारी कंपनी गजप्रोम के पास इस परियोजना का मालिकाना हक है। काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन इसे अभी तक यूरोप की एजेंसी से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

अफगान महिलाओं के लिए पर्दा जरूरी, संस्कृति बदलने की कोशिश न करे अमेरिका : तालिबान

काबुल (एजेंसी)

तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को पर्दे में रहना होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि देश में सिर्फ हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा। तालिबान ने अमेरिका को भी साफ कहा है कि वह उनके देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश न करें।

तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि महिलाओं के अधिकार को लेकर अमेरिका अपना नजरिया अफगानिस्तान पर न थोपे। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो इसे उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप माना जाएगा।

सुहैल शाहीन का कहना है कि हिजाब के बिना महिलाओं की शिक्षा का विचार पश्चिमी है। यह अफगानिस्तान की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तालिबान कतई इसके पक्ष में नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा अगर अफगानिस्तान में महिलाएं हिजाब में रहेंगी, तो महिलाओं के अधिकार को लेकर कोई मुद्दा नहीं होगा। उनका कहना है कि यहां महिलाएं हिजाब में रहकर काम कर सकती हैं। शिक्षा भी ले सकती हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिजाब न पहनी लड़कियों को यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक दिया जा रहा है और वापस लौटाया जा रहा है।

ये वीडियो काबुल के राणा यूनिवर्सिटी का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिन लड़कियों ने बुर्का या हिजाब नहीं पहना है, उन्हें गेट पर ही रोका जा रहा है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान का शासन आने के बाद से संगठन ने 1990 के दशक के नियमों को नहीं अपनाया है। लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई है, लेकिन पर्दे-बुर्के के नियमों को सख्त कर दिया गया है।

हिजाब विवाद पर प्रोपोगैंडा फैलाने में लगा पाकिस्तान, फवाद चौधरी के बाद अब इमरान के इस मंत्री ने कहा- मुस्लिम लड़कियों को डराया जा रहा

वाशिंगटन (एजेंसी)

पाकिस्तान की तरफ से एजेंडे के तहत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से प्रोपोगैंडा फैलाने में लग गया है। पहले तो इमरान के चहेते मंत्री फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना जहर उगला अब हिजाब विवाद में इमरान खान सरकार के मंत्री भी कूद पड़े हैं। पाकिस्तान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हिजाब पहनने पर मुस्लिम लड़कियों को डराया जा रहा है। कुरैशी ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना गलत है। इमरान खान के मंत्री ने हिजाब विवाद में अपना बयान देते हुए कहा कि ये मुस्लिम महिलाओंके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इससे पहले पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा, 'मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है, वह डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है। हिजाब पहनना अन्य ड्रेस की तरह से एक निजी पसंद का मामला है। नागरिकों को मुक्त होकर अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अल्लाह हू अकबर।

मलाला की भी हुई एंट्री

पाकिस्तान की महिला कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरुस्कार विजेता मलाला ने एक ट्वीट करके कहा, 'हिजाब पहने हुई लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिये पर जाने से रोकना चाहिए।

मौजूदा समय में आतंकी समूहों को अफगानिस्तान में सबसे अधिक आजादी

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में किया गया दावा

जेनेवा (एजेंसी)

आतंकवादी समूह हाल के दिनों में, अन्य देशों की अपेक्षा, अफगानिस्तान में कहीं अधिक आजादी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तालिबान ने विदेशी आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाया है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का लक्ष्य खुद को अफगानिस्तान में मुख्य प्रतिवादी ताकत के रूप में स्थापित करने की है और अपने प्रभाव को मध्य और दक्षिण एशिया के देशों तक फैलाने की है। इस आतंकी संगठन को तालिबान भी अपने प्राथमिक सशस्त्र खतरे के तौर पर देखता है। इस्लामिक स्टेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न किए गए खतरे और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से सदस्य देशों को किए जाने वाले सहयोग पर आधारित 14वीं महासचिव की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तालिबान देश में विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए कदम उठा रहा है। इसके उलट, सदस्य देश इस बात से चिंतित हैं कि हालिया इतिहास में आतंकवादी कहीं अधिक आजादी का आनंद ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान जाने वाले विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की संख्या कम है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट का नेतृत्व अब भी सनाउल्ला गफ्फारी के पास है, जो अफगान नागरिक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएस और अल कायदा प्रतिबंध समिति ने गफ्फारी को पिछले साल दिसंबर में आतंकवादियों की सूची में डाला था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस-खुरासान अफगानिस्तान में अस्थिरता का लाभ ले रहा है और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी सहित अन्य विदेशी आतंकवादी समूहों से लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों का आकलन है कि आईएसआईएस-खुरासान के लड़ाकों की संख्या 2200 से बढ़कर 4000 के करीब पहुंच रही है। यह वृद्धि तालिबान द्वारा कई लोगों को कारागारों से रिहा करने के बाद बढ़ी है। एक सदस्य का आकलन है कि आतंकी समूह के आधे सदस्य विदेशी आतंकवादी हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के इस्तेमाल और उनके प्रभाव को लेकर अमेरिका एवं उसके सहयोगियों और रूस एवं चीन के बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तनातनी हो गई।

परिषद के अध्यक्ष रूस की मेजबानी में ह्यप्रतिबंध संबंधी सामान्य मामलेः उनके मानवीय और अनपेक्षित परिणामों को रोकना विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस आयोजित की गई, जिसमें रूस ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों एवं समूहों द्वारा लागू किए गए 'एकतरफा प्रतिबंधों' की निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी ए डिकार्लो ने परिषद से कहा कि 14 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्थाएं हैंः उदाहरणार्थ वे लीबिया, माली, दक्षिण सूडान और यमन में संघर्ष के समाधान को सहयोग देती हैं, गिनी बिसाऊ में उनका उद्देश्य सरकार के असंवैधानिक परिवर्तनों को रोकना है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो और सोमालिया में वे प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाती हैं, उत्तर कोरिया में उनका मकसद हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है और वे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादी खतरों पर रोक लगाती हैं।

डिकार्लो ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों में 1990 के दशक के बाद से कई बदलाव लाए गए हैं, ताकि इनके आम नागरिकों और तीसरे देशों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े और सुरक्षा परिषद की अधिकतर प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मानवीय छूट को शामिल किया गया है और यह छूट मुहैया कराई गई है। संयुक्त राष्ट्र में बैठक की अध्यक्षता कर रहे रूस के उपराजदूत दमित्री पोलियांस्की ने कहा कि कई प्रतिबंध व्यवस्थाएं राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की योजनाओं में हस्तक्षेप करती हैं।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को उन्हें हटाने के लिए अधिक यथार्थवादी मापदंड तय करने चाहिए, ताकि उन्हें हटवाना 'कोई असंभव मिशन' नहीं बन जाएं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि प्रतिबंध एक ऐसा कारगर तरीका है, जिसके कारण 'आतंकवादियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के जरिए धन एकत्र करना मुश्किल हो जाता' है और उसने उत्तर कोरिया के परमाणु एवं बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की 'कुछ क्षमताओं' के विकास की गति को धीमा किया है।

ब्रिटेन के उप राजदूत जेम्स कारियुकी ने कहा कि अंगोला, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध की महत्ता साबित हुई है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने एकतरफा प्रतिबंधों को 'अत्यधिक हानिकारक' बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदमों ने 'लक्षित देशों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यों और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति' को बाधित किया है।

ग्रीनफील्ड ने इसके जवाब में कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय तरीके से प्रतिबंध लगाने को तरजीह देता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य देश 'शांति प्रक्रिया को बाधित करने वालों, हाई प्रोफाइल आतंकवादियों, मानवाधिकारों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को प्रतिबंध सूची में डालने' की प्रक्रिया को

बाधित करते हैं, तो अमेरिका और कई अन्य देशों को कदम उठाने पड़ते हैं।

अलग-अलग देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के गैरकानूनी होने के रूस के तर्क के जवाब में ग्रीनफील्ड ने कहा, 'अमेरिका इस बात को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।'

संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस की उप राजदूत नथाली ब्रॉडहर्स्ट ने कहा कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंध 'अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार' हैं।

सुविचार मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है - चाणक्य

संपादकीय

घोषणापत्र से उम्मीद

दो दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान होना है और मंगलवार को जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया, तब तक शायद पहले दौर का मतदान जिन इलाकों में होना है, वहां के मतदाता अपना मन भी बना चुके होंगे कि उन्हें अपना वोट किसे देना है। यह देरी बताती है कि चुनावी लड़ाई में घोषणापत्रों की भूमिका अब गौण होती जा रही है। कम से कम राजनीतिक पार्टियां इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं मानतीं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र को नाम दिया है- लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, जबकि सपा के घोषणापत्र का नाम है- वचन पत्र। कांग्रेस ने अपना महिला घोषणापत्र पिछले साल दिसंबर में ही जारी कर दिया था। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो उसका घोषणापत्र जैसी औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं है। हालांकि, सभी दल अपने घोषणापत्रों से काफी पहले ऐसी फुटकर घोषणाओं का अंबार लगा चुके हैं, जो अब चुनावी चर्चा का हिस्सा हैं। हमारे सामने अब मोटे तौर पर तीन घोषणापत्र मौजूद हैं। इन सब को एक साथ देखें, तो चुनावी वादों का जो संसार हमारे सामने है, वह काफी दिलचस्प है। भाजपा का वादा है कि पार्टी सत्ता में लौटी, तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। उसने किसानों को मुफ्त दी जाने वाली चीजों की सूची में सोलर पंप भी जोड़ दिया है। उधर समाजवादी पार्टी ने तो सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर डाला है, मुफ्त सिंचाई का वादा तो उसके घोषणापत्र में है ही। इस बार सभी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए विशेष वादे किए गए हैं। भाजपा ने कहा है कि वह निराश्रित और विधवा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन देगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने सभी गरीब ित्रयों को हर माह 1,500 रुपये पेंशन का वादा किया है। भाजपा ने कहा है कि वह 'पीएसी' जैसे पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेगी, जबकि कांग्रेस के महिला घोषणापत्र में कहा गया है कि 25 फीसदी रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कांग्रेस ने ग्रेजुएशन करने वाली हर छात्रा को स्कूटी देने की बात कही थी, इसी वादे को कुछ अलग तरह से भाजपा के संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया गया है। कांग्रेस यदि महिलाओं को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो भाजपा ने होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही है। सपा अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात कर रही है, तो भाजपा का वादा है कि हर घर से एक को नौकरी मिलेगी। भाजपा का एक वादा सबसे अलग है- 'लव जेहाद' पर दस साल की कैद। इनमें कौन से वादे पूरे होंगे, कौन से नहीं, इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग ऐसे वादों से प्रभावित होकर मतदान का फैसला करते हैं या उसे बदल सकते हैं? लोग अपनी आकांक्षाओं और अपने सपनों को साथ लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनक फैसले में घोषणापत्रों से ज्यादा भूमिका उनके निजी व सामुदायिक अनुभवों और विचारों की होती है। फिर भी घोषणापत्र महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक तो चुनाव लड़ने वाले दल कल्याणकारी मकसद का एलान करते हैं और दूसरे, यह ऐसा दस्तावेज है, जिसको लेकर उन्हें आगे चलकर कठघरे में खड़ा किया जा सकता है।

आज के कार्टुन

धर्म और विज्ञान

आचार्य रजनीश ओशो/ दुनिया में दो ही तरह के पागल लोग हैं, वे जो हमेशा अतीत की बात करते हैं, और थोड़े जो भविष्य की बात करते हैं। अतीत की बात करने वाले इतिहासविद, पुरातत्वविद् इत्यादि होते हैं। जो भविष्य की बात करते हैं वे पैगंबर, कल्पनाशील, कवि होते हैं। मैं दोनों ही नहीं हूं। मेरा सारा संबंध इस क्षण से है..अभी..यहां। मैं पैगंबर नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं और इसका असल में भविष्य से कुछ लेना-देना नहीं है। यह अभी यहीं घट रहा है। लोग अंधे हैं, इसलिए देख नहीं सकते। मैं देख सकता हूं, यह पहले ही हकीकत बन चुका है। बड़ी से बड़ी बात जो हो रही है-जो बाद में समझ में आएगी, वह है धर्म और विज्ञान का मिलन, पूर्व और पश्चिम का मिलन, भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिलन, बाह्य और अंतस का मिलन, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी का मिलन, लेकिन यह अभी ही हो रहा है, यह भविष्य में विकसित होगा, लेकिन मेरा संबंध वर्तमान से है, और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कुछ बहुत ही महान बात होने को है। एडिंग्टन अपनी आत्मकथा में कहता है, 'जब मैंने अपने जीवन की शुरु आत एक वैज्ञानिक की तरह की तो मैं सोचता था कि दुनिया चीजों से चलती है, लेकिन जैसे मैं विकसित हुआ, वैसे-वैसे मैं अधिक से अधिक सचेत हुआ कि दुनिया में सिर्फ चीजें ही नहीं होती बल्कि विचार भी होते हैं।' मेरी अपनी दृष्टि यह है कि हमें जोरबा दि बुद्धा का निर्माण करना होगा। जो नया बुद्ध होगा वह जोरबा दि ग्रीक और गौतम बुद्ध का मिलन होगा। यहां कई तरह के वैज्ञानिक हैं। कवि और संगीतकार, चित्रकार हैं-सभी तरह के लोग, और ये सभी एक साथ एक महान प्रयास के लिए जुटे हैं - ध्यान के लिए। यहां सिर्फ एक मिलन का बिंदु है, और वह है ध्यान। सिर्फ एक बिंदु पर वे मिलते हैं, अन्यथा सभी की अपनी वैयक्तिक यात्रा है। इस मिलन द्वारा अद्भुत विस्फोट संभव है। जिनके पास आंखें हैं, वे यह घटते यहां देख सकते हैं। पृथ्वी पर यही एक जगह है जहां दुनिया के सारे देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे। हम यहां पर रूस के लोगों को चूक रहे थे और अब मैं यह बताते प्रसन्न हूं कि रूस से भी लोग यहां आ गए हैं। सभी वर्ग यहां मिल रहे हैं, सभी धर्म यहां मिल रहे हैं। यहां पर छोटा सा संसार है, छोटी सी दुनिया, और हम सभी यहां पर मानव की तरह मिल रहे हैं। कोई ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है या मुसलमान नहीं है। कोई नहीं जानता कि कौन वैज्ञानिक है, कौन संगीतकार है, कौन चित्रकार है, कौन प्रसिद्ध अभिनेता है। कोई कहता भी नहीं..।

बुलंद इरादों के साथ चाहिए प्रभावी कार्यान्वयन

- गिरीश्वर मिश्र

अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की मानें तो सुख या खुशहाली के मूल में धर्म होता है। इस धर्म के मूल में अर्थ यानी विविध प्रकार के संसाधन की व्यवस्था होती है। सुनने में धर्म का मूल अर्थ में ढूढ़ना कुछ असंगत-सा लगता है पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का संबंध नैतिक मानदंड के पालन से है और वह वस्तुत- आचरण का प्रश्न बन जाता है और उसका प्रमुख माध्यम स्वयं मनुष्य का शरीर ही होता है। इसीलिए शरीर को साधन कहते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं- शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। शरीर ठीक तरह चले, स्वस्थ रहे इसके लिए उचित आहार, विहार, मनन और मनोरंजन की अपेक्षा होती है। यानी अन्न, जल, व्यवसाय और उत्पादन आदि आर्थिक कार्य भी होने चाहिए। इसलिए धर्म के मूल को अर्थ में पाना उचित जान पड़ता है। अपनी विचार श्रृंखला के अंत में निष्कर्ष रूप में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'राज्य के समृद्ध होने से प्रजा भी सुखी होती है।' अर्थात यदि राज-कोष परिपूर्ण हो तो आम जन भली-भाँति सुख चैन से रह सकेंगे और उनमें आश्वस्ति कि अनुभूति और जीवन की सार्थकता का अहसास होगा। यह कहने के पीछे यही भाव है कि राज्य के पास यदि पर्याप्त संसाधन हों तो वह प्रजा के सुख के लिए सुविधाएं और साधनों की व्यवस्था करेगा। आचार्य चाणक्य की इस अर्थ नीति को यदि विस्तार में समझा जाय तो वित्त व्यवस्था और उसके नियोजन-नियमन की गतिकी (डायनेमिक्स) कुछ-कुछ समझ में आने लगती है। देश का बजट भी सरकार और प्रजा के बीच इन्हीं रिश्तों का खाका प्रस्तुत करता है। दायित्व सरकार और प्रजा दोनों पक्षों का बनाता है। दोनों मिलकर देश बनाते हैं और दोनों को मिलकर देश चलाना चाहिए। हाँ, सरकार का दायित्व दुहरा हो जाता है क्योंकि उसे जनता की दृष्टि भी समझनी होती है और जनता पर शासन भी करना पड़ता है। केंद्र सरकार का वार्षिक बजट देश-मन की मुराद पूरी करने वाले नुस्खे की तरह होता है। समाज के सभी वर्ग हर साल इस आस के साथ इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इस बार कहाँ और कितनी राहत मिलने वाली है और जीना आसान हो सके। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक जीवन की आपसी परिधि से बाहर निकल कर औपचारिक तंत्र के अधीन होती गईं और आर्थिक नियोजन सरकारी व्यवस्थाओं के अधीन होता गया। पर अर्थ होने बाद अर्थ या वित्तीय संसाधनों की बदौलत ही जीवन में रस का प्रवाह हो पाता है इसलिए लोग बड़ी उत्सुकता के साथ बजट प्रावधानों के प्रकट और निहित अभिप्राय ढूढने की कोशिश करते हैं। बजट के प्रावधानों के साथ और उनके बीच ही जीने का सारा कारोबार होता है। इस बार का बजट इस अर्थ में ख़ास है कि दो साल लम्बी चली कोविड की वैश्विक महामारी झेलने के बाद कमरतोड़ आकस्मिक खर्चों के सिलसिले पर कुछ अंकुश लगाने के बाद यह पेश हुआ है। आवागमन की बंदिशों के साथ ही आम जनों के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर भी कम पड़ते गए। महामारी ने सामान्य जीवन को तो अस्त-व्यस्त किया ही अनेक स्तरों पर व्यापार-वाणिज्य में पहल के अवसरों पर भी उसका बुरा अवसर पड़ा। इस बीच बढ़ती महंगाई की मार और रोजगार के अवसरों की कमी के चलते हताशा के स्वर भी उठाते रहे जो स्वाभाविक भी है। स्कूली बच्चों और युवा विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा से ऊब और घुटन होती रही। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर समझौते हुए। दफ्तरों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस तरह से बदलते परिवेश में बजट को लेकर सबके मन में उत्सुकता थी कि इस बार क्या कुछ मिलेगा। जो बजट पेश हुआ वह सिर्फ एक ही सरोकार से जुड़ा था कि आज की विकट परिस्थितियों में देश को आर्थिक मजबूती कैसे दी जाय। प्रस्तुत किए गए बजट को किसी भी तरह लोकप्रिय या फिर चुनावी तैयारी वाला घोषणा पत्र नहीं कहा जा सकता। इन सबसे दीगर बजट में देश की जरूरतों और जमीनी हकीकत को पहचान कर आ रहे बदलाव को गहनता से समझने की कोशिश की गई। इसमें बहुतों को आशा के विपरीत दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर व्यापक धरातल पर सोचने की सार्थक कवायद साफ़ झलक रही है। इससे सरकार की नेकनीयत और समावेशी लोक-कल्याण की मंशा और सोच भी प्रकट होती है। सरकार की प्राथमिकताएं साफ़ दिख रही हैं। अमृतकाल में आगे के पचीस साल की योजना बनानी है। यह नीतिगत एजेंडा पेश करता दिखता है। कोरोना महामारी से उबरती अर्थव्यवस्था में प्राण-संचार के लिए बजट में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जरूरी अवसंरचना पर विशेष खर्च किया जाना तर्कसंगत है। बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देते हुए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। विश्व के आर्थिक क्षितिज पर भारत के आगे बढ़ने की आहट सुनी जा सकती है। गौरतलब है कि महामारी के मद्देनजर दो सालों में कर नहीं बढ़ाया गया। इस बार आयकर की दरें पूर्ववत बरकरार रखी गईं हैं। करदाताओं को जरूर अपने आयकर रिटर्न को सुधारने का अवसर दिया गया है। बजट में देश के विकास की नींव को मजबूत करने के अनेक प्रस्ताव दे गए हैं। देश में पचीस हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार होंगे। 5 जी स्पेक्ट्रम कि नीलामी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी यातायात की स्थिति सुधारने के लिए सड़क के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। तीन सालों में चार सौ वन्दे मातरम ट्रेनों को चलाया जायगा। इन सबसे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कामकाज में भी सुविधा होगी। साठ लाख नई नौकरियों की भी घोषणा की गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्व की बातें की गई हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा को लेकर सोलह हजार करोड़ के अनुदान की बढ़ोत्तरी हुई है। यह संतोष की बात है कि बारहवीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की जायगी। मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा की दिशा में यह प्रभावकारी कदम होगा। वर्चुअल प्रयोगशालाओं की मदद से गणित और विज्ञान की शिक्षा को सुदृढ़ किया जायगा। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर को स्थापित करने का अवसर होगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रगतिशील और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। दो सौ ई-विद्या टीवी चैनेल चलेंगे। देश में शिक्षा की जरूरतों को लेकर सरकार चिंतित जरूर है पर बजट का आवंटन अपर्याप्त है। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है। यह हर्ष की बात है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार एमएसपी के अंतर्गत गेहूँ और धान की खरीदी के लिए 2.37 लाख करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है। कुल 1008 मीट्रिक तन अनाज खरीदा जायगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जायगा। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवा प्रदान करने के साथ तिलहन के उत्पाद को बढ़ाने के उपाय भी किये जाएंगे। कृषि ऋण के लिए 18 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्टार्ट अप को गति दी जायगी।कोरोना काल में पिछड़ने की भरपाई के लिए ये सारे प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे।

ऑनलाइन शिक्षा के नुकसान की भरपाई कैसे हो?

ललित गर्ग

कोरोना महामारी के कारण बच्चों के शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ा है। लंबे समय तक स्कूल बंद होने से बच्चों के सीखने के स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, अब देश के शिक्षण संस्थानों ने सामान्य हालात की ओर कदम बढ़ा दिये हैं। सोमवार को देश के बहुत से प्रदेशों में स्कूल-कॉलेज खुल गए, उनके परिसरों में पुरानी रौनक लौट आई। लगभग दो वर्षों बाद कंधों पर बस्ते लादे स्कूल जाते छोटे-छोटे बच्चों को देखना संभव हुआ है, जो सुखद अहसास का सबब बन रहा है। देश के ज्यादातर प्रदेशों में कक्षा नौ से ऊपर की सभी कक्षाओं की पढ़ाई सोमवार से शुरू हो गई है, जबकि एकाध राज्य में इसका उल्टा तरीका अपनाया गया है। वहां छोटे बच्चों के स्कूल पहले खोले गए हैं। यह अच्छी बात है कि देश के तकरीबन सभी राज्य एक साथ महामारी के दौर में ठहरी हुई शिक्षा-व्यवस्था को सामान्य बनाने में जुट गए हैं। इस समय जब नए संक्रमितों की दैनिक संख्या और संक्रमण की दर, दोनों नीचे आ रहे हैं, तब इस तरह का फैसला स्वाभाविक ही था, शिक्षा पर पसरे सन्नाटे को दूर करने के लिये यह नितांत अपेक्षित भी हो गया था। कोरोना महामारी से शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित एवं निस्तेज हुई है। स्कूलों के बंद होने से बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए क्योंकि महामारी के दौरान सभी बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी। भारत में 6-13 वर्ष के बीच के 42 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं करने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष (यूनिसेफ) की एक रिपोर्ट में सामने आयी है। रिपोर्ट कहती है कि इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें, वर्कशीट, फोन या वीडियो कॉल, व्हाट्सऐप, यूट्यूब, वीडियो कक्षाएं आदि का इस्तेमाल नहीं किया है। बहरहाल, सर्वेक्षण में पाया गया है कि स्कूलों के बंद होने के बाद अधिकतर छात्रों का अपने अध्यापकों के साथ बहुत कम संपर्क रहा। रिपोर्ट में कहा गया है, 5-13 वर्ष की आयु के कम से कम 42 प्रतिशत छात्र और 14-18 वर्ष की आयु के 29 प्रतिशत छात्र अपने शिक्षकों के संपर्क में नहीं रहे। कोरोना काल के दौरान खाली रहने से बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 80 प्रतिशत छात्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने के स्तर में कमी आयी है। बार-बार स्कूल बंद होने से बच्चों के लिए सीखने के अवसरों में चिंताजनक असमानताएं पैदा हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास का ठीक से न चल पाना, इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधाओं का न होना और पढ़ाई के प्रति अरूचि ने बच्चों को शिक्षा के लिहाज से पीछे धकेल दिया है। हाल यह है कि अब उन्हें भाषा और गणित में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों की शिक्षा से जुड़े नुकसान का आंकलन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा की गयी एक फील्ड स्टडी में पाया गया कि कोरोना के बीच स्कूल बंद होने से बच्चों ने पिछली कक्षाओं में जो सीखा था वो उसे भूलने लगे हैं। इसकी वजह से वर्तमान सत्र की कक्षाओं में उन्हें सीखने में दिक्कत आ रही है। स्कूल खुलने के साथ एक अहम बात जो इनमें देखने को मिल रही है कि किताबों को पढ़कर अर्थ समझने में भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। पढ़ाई में गैप आने की वजह से उनमें अभी वह तेजी देखने को नहीं मिल रही। इसलिए बचे हुए सत्र में छात्र और शिक्षक दोनों को कम समय में दोगुनी मेहनत करनी होगी। महामारी के खतरों को देखते हुए स्कूलों को खोला जाए या नहीं, इसे लेकर पिछले दो साल में पूरी दुनिया में खासी जद्दोजहद होती रही है। कोरोना वायरस से हरेक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के प्रयास में बच्चों की शिक्षा का हरण कर लिया गया। बच्चों के हितों के बलिदान की भरपाई के लिए, सरकारों को अंततः इस चुनौती के लिए कमर कसना जरूरी हो गया और सभी बच्चों के लिए तत्काल स्कूलें खोलना जरूरी हो गया। अमेरिका आदि अनेक देशों में तो महामारी की पहली लहर के बाद ही स्कूल खोलने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। लेकिन तब परिणाम अच्छे नहीं रहे थे। तभी यह खतरा भी समझ में आया था कि कोरोना वायरस भले बच्चों को शिकार नहीं बनाता, लेकिन कुछ बच्चे अगर इस वायरस को लेकर घर पहुंचते हैं, तो वयस्कों और बुजुर्गों को इससे खतरा हो सकता है। इस दो साल में पूरी दुनिया ने स्कूलों के गेट बंद कर ऑनलाइन शिक्षा की संभावनाएं और सीमाएं भी समझ ली हैं। यह भी समझ में आ गया है कि इस माध्यम से बच्चों को शिक्षित तो किया जा सकता है, लेकिन उनका पूरा मानसिक विकास नहीं हो सकता। महामारी के दौर भारत में तो स्कूलों में सभी छात्रों को समान रूप से दूरस्थ शिक्षा देने की पूरी तरह तैयारी भी नहीं थी। इसका कारण सरकारों की अपनी शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और असमानताओं को दूर करने, या घरों में सस्ती, सुचारू बिजली जैसी बुनियादी सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने या सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी नाकामयाबी है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित होने के अधिक आसार थे क्योंकि वे पर्याप्त डिवाइस या इंटरनेट नहीं खरीद सकते थे। ऐतिहासिक रूप से कम संसाधनों वाले स्कूलों ने, जिनके छात्र पहले से ही शिक्षा संबंधी बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे थे, ने डिजिटल सीमाबद्धताओं के समक्ष अपने छात्रों को पढ़ाने में विशेष कठिनाइयों का सामना किया। भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र और शिक्षक इन तकनीकों का सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें। एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा एक अभिशाप बन गयी। ऑनलाइन शिक्षा संगी-साथियों का विकल्प नहीं दे सकती। स्कूलों में जब बच्चे एक-दूसरे से मिलते हैं, तो वे सामाजिक संबंधों का ककहरा भी सीखते हैं।

सू-दोकू नवताल 2042

	9	3						
	7			1	8			9
		8	7	3		1		
	8	9		5	1		7	6
2								5
5	1		8	7		4	9	
		4		6	5	7		
7			3	2			5	
						6	4	

सू-दोकू -2041 का हल

3	1	6	5	4	2	9	7	8
9	4	5	8	7	1	6	2	3
7	2	8	3	9	6	1	4	5
8	3	1	9	5	4	2	6	7
2	5	9	6	3	7	8	1	4
4	6	7	2	1	8	3	5	9
5	7	2	1	8	9	4	3	6
1	8	3	4	6	5	7	9	2
6	9	4	7	2	3	5	8	1

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 X 3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

फिल्म वर्ग पहेली- 2042

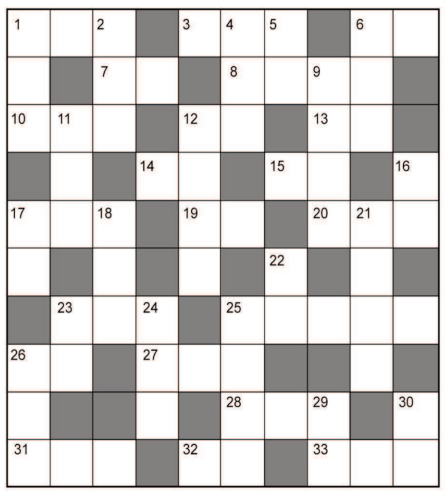

बायें से दायें:-

1. जैकी श्रॉफ, सलमान, रंभा, अश्विनी भावे की फिल्म-3
3. 'छम छम बरसा' गीत वाली फिल्म-3
6. 'जलता है जिया मेरा भीगी भीगी' गीत वाली फिल्म-2
7. राकेश रोशन, सिम्मी की फिल्म-2
8. अमिताभ, शर्मिला, हेमा, परवीन की फिल्म-4
10. 'मरना तेरी गली में जीना तेरी' गीत वाली फिल्म-3
12. फरदीन, करीना की 'रंग दीन्ही रंग' गीत वाली फिल्म-2
13. 'कहना है तुम' गीत वाली आमिर, मनीषा की फिल्म-2
14. 'सिर्फ संडे को करती हूँ मैं तो प्यार' गीत वाली फिल्म-2
15. 'चाँदनी रात है' गीत वाली सलमान, नगमा की फिल्म-2
17. 'जिंदगी ये जिंदगी दो घड़ी की जिंदगी' गीत वाली फिल्म-3
19. नागार्जुन, उर्मिला की फिल्म-2
20. जैकी श्रॉफ, जूही, एकता की एक सस्पेंस फिल्म-3
23. मिलिंद, विक्रम सलूज की फिल्म-3
25. विनोद मेहरा, अनिल कपूर, स्मिता, रति की फिल्म-2,1,2
26. 'याइला रे लड़की मस्त' गीत वाली फिल्म-2
27. धर्मेन्द्र, शर्मिला की 'बहारों की बारात आ' गीत वाली फिल्म-3
28. 'तुझे देखके दिल' गीत वाली फिल्म-3
31. सनी, जॉन, सुनील शेट्टी की फिल्म-3
32. 'जिस का मुझे था' गीत वाली अमिताभ, जीनत की फिल्म-2
33. अक्षय, सैफ, रवीना टंडन, सोनाली बेंद्रे की फिल्म-3

ऊपर से नीचे:-

1. 'रंग भरे मौसम से' गीत वाली फिल्म-3
2. अमिताभ, संजीव, ऋषि, हेमा, शर्मिला की फिल्म-3
4. 'मैं तेरी मुहब्बत में' गीत वाली फिल्म-3
5. बिजॉय आनंद, कृतिका पाने, सोनू वालिया की फिल्म-2
6. 'दिल्ली की सर्दी' गीत वाली फिल्म-3
9. राजबब्बर, अनिता की फिल्म-4
11. 'किसी के दिल में' गीत वाली फिल्म-3
12. नवीन निश्चल, सायरा की 'इधर गया था' गीत वाली फिल्म-4
16. 'तेरे बिना तेरे' गीत वाली फरदीन, करीना की फिल्म-2
17. संजय, उर्मिला की 'ओ भंवरे देखो हम' गीत वाली फिल्म-2
18. 'खाई है रे हमने कसम संग रहने की' गीत वाली फिल्म-3
21. जैकी, नीलम की 'चुराया तूने दिल' गीत वाली फिल्म-4
22. 'अपनी चाहतों पे काबू' गीत वाली जॉन, उदिता की फिल्म-2
23. इरफान खान, की 'मैंने दिल से कहा' गीत वाली फिल्म-2
24. 'हम तीनों की वो यारी' गीत वाली फिल्म-3
25. राजेंद्रकुमार, राखी की फिल्म-2,2
26. 'पहली बार जो' गीत वाली फरदीन, उर्मिला की फिल्म-3
29. 'सुन जरा सोनिये' गीत वाली फिल्म-2
30. रणधीरकपूर, बबीता की फिल्म-2

फिल्म वर्ग पहेली-2041

नदी पर बनाया जाता है बर्फ का होटल, दूर-दूर से ठहरने आते हैं पर्यटक!

दुनियाभर में कई तरह के घुमक्कड़ होते हैं जो तरह-तरह की जगह जाना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अजीबो-गरीब होटल देखना या वहां ठहरना भी पसंद होता है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही शौक रखते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे ही अजीबो-गरीब होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए मशहूर है।

कुछ अलग दिखने की सूची में स्वीडन में मौजूद आइस होटल शमिल है। ये अपने हटके प्रस्तुति के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काफी पुराना होने के बावजूद भी ये होटल अपने कलाकारी के लिए लोगों के बीच आकर्षित है। यहां हर साल कलाकार अलग-अलग कलाकारियां करते हैं। आइए आपको आइस होटल की अन्य खासियत के बारे में बताते हैं, जो आपको हैरान कर सकती हैं...

नदी पर बना हुआ होटल

स्वीडन के टॉर्न नदी के ऊपर आइस होटल बना हुआ है। ये होटल पूरी तरह से बर्फ का बना

हुआ होता है। इसकी खासियत है कि ये पिघलकर नदी का रूप ले लेता है। तय समय तक ये आइस होटल रहता है और फिर हर साल इसे बनाया जाता है। हर साल ये अलग-अलग आकर और कलाकारियों के साथ बनाया जाता है। जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां ठहरने के लिए पर्यटकों को 1 साल पहले ही बुकिंग करनी होती है।

अप्रैल के बाद पिघलना शुरु हो जाता है होटल

जब तक मौसम ठंडा और बर्फदार रहता है तब तक ये होटल अपने ठोस आकार में नदी पर मौजूद रहता है। वहीं, तापमान गर्म होने पर ये पिघलकर पानी में बदल जाता है। इसे हर साल नए-नए डिजाइन में बनाया जाता है। यहां आकार दुनियाभर के कलाकार अपनी कलाकारियां दिखाते हैं।

काफ़ी कम तापमान के होते हैं कमरे

सोलर पॉवर कूलिंग की मदद से होटल के कमरों को बनाया जाता है। यहां ज्यादातर लाइट्स या अन्य उपकरणों को सौर ऊर्जा से ही चलाया जाता है। ये होटल इकोफ्रेंडली होने के कारण लोगों के लिए पहली पसंद में से एक है। यहां के कमरों का तापमान काफी कम होता है। बर्फ की मोटी-मोटी परत को काटकर कमरा बनाया जाता है। गर्मी आने तक ये होटल बर्फ के तौर पर रहता है और फिर अप्रैल के बाद पिघलना शुरु हो जाता है।

बर्फ के सेरेमनी हॉल और रेस्त्रां भी मौजूद

साल 1992 में पहली बार ये होटल खोला गया था। यहां मौजूद रेस्त्रां, सेरेमनी हॉल और कॉम्प्लेक्स को बर्फ से ही बनाया जाता है। इतना ही नहीं, होटल के फर्नीचर, दीवार, बार समेत अन्य चीजों को भी बर्फ से ही बनाया जाता है। यहां एक से एक डिजाइनिंग वाले कमरे मौजूद हैं।

कम से कम खर्च में घूमने के लिए अपनाएं यह टिप्स, जेब पर नहीं पड़ेगा जोर

घूमना आखिरकार किसे अच्छा नहीं लगता। हर दिन के तनाव और रूटीन से ब्रेक लेते हुए नई जगहों को एक्सप्लोर करने का अपना एक अलग ही आनंद है। लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार चाहकर भी घूमने नहीं जा पाते और उसकी वजह होती है बजट। चार-पांच महीने में अगर एक बार भी घूमने का प्लॉन बनाया जाए तो इससे पूरा बजट बिगड़ जाता है और सेविंग भी काफी हद तक खर्च हो जाती है। हो सकता है कि आप भी पैसों के चक्कर में घूमने ना जा रहे हों। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिसे अपनाकर आप ट्रेवलिंग के दौरान पैसों की भी बचत कर सकते हैं-

प्लान करें ट्रिप

जब आप किसी नई जगह पर घूमने का विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें आपके काफी सारे पैसे खर्च ना हो तो इसके लिए आपको अपनी ट्रिप को प्लॉन करना चाहिए। आप जहां जा रहे हैं, इसके लोगों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और भोजन आदि के बारे में थोड़ा-बहुत जानना आपको बहुत परेशानी से बचाएगा। इसके अलावा रिसर्च आपको उन महंगे शहरों के बारे में बताएगा जिनसे आप बचना चाहते हैं। रिसर्च के जरिए आप उस जगह की सस्ती जगहों व लोकल फूड के बारे में जान पाएंगे।

सोच-समझकर चुनें एयरलाइन

यदि आप अपनी यात्रा के लिए सही एयरलाइन नहीं चुनते हैं तो आपको फ्लाइंग पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ सकता है।एक बजट एयरलाइन आपको कुछ पैसे बचा सकती है, इसलिए ट्रेवल के लिए आप सोच-समझकर एयरलाइन बुक करें। साथ ही अलग-अलग समय पर फ्लाइंग के चार्जेस अलग होते हैं, इसलिए उस पर भी फोकस जरूर करें।

ऑफ-सीजन में यात्रा करें

यह एक ऐसी ट्रिक है, जो ट्रेवल के दौरान आपके काफी सारे पैसे खर्च होने से बचा सकती है। पीक सीज़न के दौरान यात्रा करने से आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए पीक सीज़न की यात्रा से बचना समझदारी है। एयरलाइंस, होटल और फूड प्राइस आदि छुट्टियों के दौरान और क्रिसमस, ईस्टर, ईद और दिवाली जैसे अवसरों पर बढ़ जाती हैं। ऐसे में आप ऑफ सीजन में घूमने का प्लॉन करें। इससे आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और भीड़ कम होने के कारण आप अच्छी तरह एंजॉय भी कर पाएंगे।

खाएं लोकल फूड

अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं तो आपको अपने फूड पर भी फोकस करना चाहिए। ओवरप्राइज्ड कैफ़े और रेस्तरां में आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं जिन्हें आप स्थानीय स्थानों पर जाकर बचा सकते हैं जो ताजा भोजन परोसते हैं। इससे एक लाभ यह भी होगा कि आपको उस जगह के ऑथेंटिक फूड का स्वाद चखने का मौका मिलेगा।

हैप्पी हनीमून

करना है पॉकेट फ्रेंडली हैप्पी हनीमून तो घूमें इन जगहों पर

शादी के बाद हनीमून किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए एक यादगार वक्त होता है। हनीमून ट्रिप को लेकर कपल्स के मन में कई तरह की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन बहुत से कपल्स सिर्फ इसलिए हनीमून पर नहीं जा पाते, क्योंकि वह उनकी पॉकेट से बाहर होता है। हो सकता है कि आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप कम बजट में हैप्पी हनीमून ट्रिप प्लॉन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इन जगहों पर जा सकते हैं-

हिमाचल प्रदेश

दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहां पर आप कम बजट में अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। यह आध्यात्मिक गुरु, दलाई लामा का घर है और इसमें कई जगह हैं, जैसे कि भागसू फॉल्स, शिव कैफ़े आदि जगहों पर जा सकते हैं और ट्रेकिंग और अन्य एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहां पर आपको व्यक्ति प्रति दिन 300 रूपए में ठहरने की जगह मिल सकती है।

केरल

केरल एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है और न्यू कपल्स के लिए इसे एक बेहतरीन घूमने की जगह माना जाता है। यहां की नेचुरल ब्यूटी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। केरल को भगवान का अपना देश माना जाता है, जिस कारण हर व्यक्ति केरल के मंदिरों को देखना चाहता है। यहां बहुत सिद्ध मंदिर हैं। कुछ मंदिरों में पद्मनाभस्वामी मंदिर, गुरुवायुर मंदिर, वडक्कुन्नत मंदिर, अनंतपुरा झील मंदिर, थिरुमन्धाकुन्नु मंदिर, पडियानूर देवी मंदिर आदि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह पद्मनाभस्वामी मंदिर है जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है।

उदयपुर

राजस्थान राज्य में कई बेहतरीन घूमने की जगहे हैं, लेकिन आप कम बजट में राजस्थान में हनीमून पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उदयपुर जाना चाहिए। यह अपेक्षाकृत काफी सस्ता है। आप यहां पर सिटी पैलेस से लेकर पिंचोला झील आदि कई खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं।

आगरा

आगरा के ताजमहल को दुनिया के सात अजूबों में शामिल किया गया है। यह बेमिसाल प्यार की निशानी है। ऐसे में आपके लिए आगरा से बेहतर घूमने की जगह कौन सी होगी। यहां घूमने में आपको 5000 रूपए से भी कम का खर्च आएगा। आगरा में आप ताजमहल के अलावा आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी आदि घूम सकते हैं। वैसे अगर आप आगरा जा रहे हैं तो वहां का फेमस पेठा खाना ना भूलें।

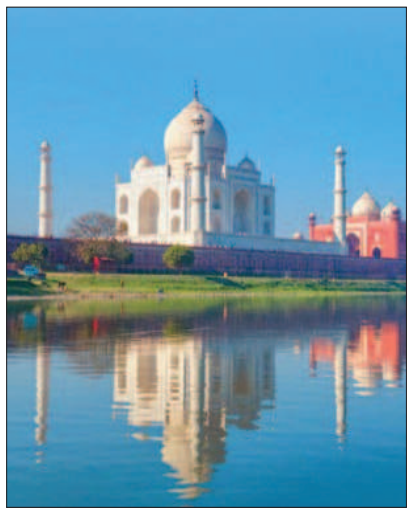

झारखंड में दो कोयला ब्लॉकों के लिए डालमिया सीमेंट ने लगाई सबसे ऊंची बोली

नई दिल्ली(एजेंसी)। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड झारखंड में दो कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए हुई नीलामी में सबसे बड़ी बोलीकर्ता के रूप में उभरी है। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ओडिशा में एक कोयला ब्लॉक के लिए महानदी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे बड़ी बोली लगाई है जबकि पूर्वी ओडिशा में एक अन्य कोयला ब्लॉक के लिए सबसे बड़ी बोली याजदानी स्टील एंड पावर लिमिटेड ने लगाई है। इसी तरह असम में एक कोयला खदान के लिए सबसे बड़ी बोली असम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड ने लगाई है।

कोयला मंत्रालय ने नीलामी के पहले दिन पांच कोयला ब्लॉक के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। इनमें से चार कोयला खदानों का पूरी तरह अन्वेषण हो चुका है जबकि एक खदान का आंशिक अन्वेषण हुआ है।

बयान के मुताबिक, नीलामी के लिए रखी गई इन पांचों कोयला खदानों की सम्मिलित भंडार क्षमता 118.81 करोड़ टन है। इनसे सालाना 59.44 लाख टन कोयले का उत्खनन किया जा सकता है।

भारतीय उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों की दिलचस्पी बढ़ी : रिपोर्ट

नयी दिल्ली(एजेंसी)। भारत में अब आवागमन वाले वाहनों का रुझान बदल रहा है और ज्यादा उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। डेलॉयट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। डेलॉयट की तरफ से जारी वैश्विक ऑटोमोटिव उपभोक्ता अध्ययन रिपोर्ट, 2022 कहती है कि एक-तिहाई से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के प्रति दिलचस्पी दिखाई है। इसके मुताबिक, भारत में पर्यावरण-अनुकूल और महामारी की वजह से टिकाऊ परिवहन साधनों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 59 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण स्तर और पेट्रोल एवं डीजल वाहनों के उत्सर्जन को लेकर फिक्रमंद हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों में भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि का पता चलता है क्योंकि वे उत्सर्जन एवं प्रदूषण में कमी लाने में मददगार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, हरित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा बजट 2022-23 में भी की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की अदला-बदली की सुविधा चार्जिंग स्टेशनों पर देने से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। डेलॉयट इंडिया के साझेदार एवं ऑटोमोटिव प्रमुख राजीव सिंह ने कहा, ''उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों और नवाचारी खोज सामने आने से भारतीय वाहन उद्योग वृद्धि का नया दौर देखने जा रहा है। हमारा नया अध्ययन ग्राहकों की बदलती धारणाओं का जिक्र करता है।' उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों की वृद्धि को मजबूती मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

आवास वित्त कंपनियों के ऋण पोर्टफोलियो में 8-10प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

मुंबई। आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के ऋण पोर्टफोलियो की वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 8-10 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में नौ-11 प्रतिशत रहेगी। इक्रा की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। इक्रा रेटिंग्स ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों का ऋण वितरण दूसरी तिमाही में सुधरा है। पहली तिमाही में उनका पोर्टफोलियो करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो साल भर पहले की समान अवधि के मुकाबले नौ प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही और उसके बाद भी पोर्टफोलियो वृद्धि का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। आवास ऋण की मांग अच्छी रहने, आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते स्तर और देश में टीकाकरण की ऊंची दर से पोर्टफोलियो वृद्धि को मजबूती मिलेगी। रेटिंग एजेंसी के उपाध्यक्ष एवं वित्तीय क्षेत्र रेटिंग प्रमुख सचिन सचदेवा ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि वर्ष 2021-22 में एचएफसी का पोर्टफोलियो 8-10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। वहीं वर्ष 2022-23 में इसकी वृद्धि दर 9-11 प्रतिशत रहने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि महामारी से उपजे आघात के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से आवास ऋण वृद्धि की स्थिति तेजी से सुधरी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत में एचएफसी का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 3.6-3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि पहले इसके 3.3-3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

इक्विटी म्यूचुअल फंड को जनवरी में मिला 14,888 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश

नयी दिल्ली। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनवरी, 2022 में 14,888 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया है। यह लगातार 11वां महीना है जब शुद्ध रूप से मासिक प्रवाह बढ़ा है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के निकाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा दिसंबर, 2021 में 25,077 रुपये के शुद्ध प्रवाह की तुलना में काफी कम है। इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं में शुद्ध रूप से प्रवाह मार्च, 2021 से लगातार जारी है और इस दौरान शुद्ध रूप से एक लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ। यह म्यूचुअल फंड की इक्विटी से जुड़ी योजनाओं के प्रति निवेशकों के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। इससे पहले इस तरह की योजनाओं से लगातार आठ माह जुलाई, 2020 से फरवरी 2021 के बीच 46,791 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। उद्योग के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) जनवरी के अंत में बढ़कर 38.88 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गईं, जो दिसंबर के अंत में 37.72 लाख करोड़ रुपये थीं।

सोना 247 रुपये चमका, चांदी में 825 रुपये का उछाल

नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजाार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोना 247 रुपये की बढ़त के साथ 48,403 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,156 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी के अनुरूप चांदी भी 825 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 62,417 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61,592 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,827 डॉलर प्रति औंस पर था। वहीं चांदी 23.17 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, कॉमेक्स में सोना 1,827 डॉलर प्रति औंस पर था। इससे यहां भी सोने की कीमतों में तेजी आई।

सीसीआई ने डम्पर ट्रक यूनियन को प्रतिस्पर्धा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डम्पर एंड डम्पर ट्रक यूनियन लाइमस्टोन को अनुचित कारोबारी गतिविधियों का दोषी पाते हुए इनसे दूर रहने को कहा है। कारोबारी शुचिता सुनिश्चित करने वाले नियामक सीसीआई ने कहा कि डम्पर एंड डम्पर यूनियन को निर्धारित मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह आदेश सीजे डार्सेल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की तरफ से दायर शिकायत पर आया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि जैसलमेर के सानू माइंस क्षेत्र में सक्रिय डम्पर यूनियन ने परिवहन सेवाओं की कीमत संगठित रूप से तय की और ऐसी सेवाओं की व्यवस्था को सीमित एवं नियंत्रित करने की भी कोशिश की। आयोग ने कहा कि सीजेडी लॉजिस्टिक्स को अपने वाहनों के जरिये परिवहन सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा यूनियन से जुड़ी गाड़ियों और ड्राइवरों को ही महंगी दरों पर ले जाने की बाध्यता रखी गई। आयोग ने इस मामले की पड़ताल के बाद आरोपों को सही पाते हुए कहा कि डम्पर ट्रक यूनियन और उसके सदस्य ऐसी गतिविधियों को तत्काल बंद करें और आगे भी इससे परहेज करें।

कश्मीर पर ट्वीट को लेकर डोमिनोज, होंडा ने माफी मांगी

बिजनेस डेस्क(एजेंसी)। पिज्जा कंपनी डोमिनोज और जापानी कार विनिर्माता कंपनी होंडा ने अपने पाकिस्तानी कारोबारी सहयोगियों की तरफ से सोशल मीडिया पर कश्मीर के अलगाववादियों के समर्थन में की गई टिप्पणियों से भारत में 'भावनाओं को ठेस पहुंचने' पर खेद जताया है। डोमिनोज इंडिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह भारतीय बाजार के लिए प्रतिबद्ध है और वह ''25 साल से भी अधिक समय से इसे घर मानती आ रही है और देश की जनता, संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना के प्रति सम्मान का भाव रखती है।'' पिज्जा श्रृंखला ने कहा, ''हम यहां उसकी (भारत की) विरासत को हमेशा के लिए संरक्षित करने के लिए खड़े हैं। देश हमें जो भी देता है हम उसका सम्मान करते हैं।'' कंपनी ने आगे कहा, ''देश के बाहर वाले डोमिनोज के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित अवांछित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।'' होंडा कार्स इंडिया की कंपनी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ट्विटर पर बयान पोस्ट किया, '' होंडा हर उस देश के कानूनों और करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें वह काम करती है। किसी भी तरह की ठेस पहुंचने के लिए हमें खेद है।'' भावनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें वह काम करती है। किसी भी तरह की ठेस पहुंचने के लिए हमें खेद है।'' कंपनी ने कहा, ''किसी भी सहयोगी, डीलर अथवा हितधारक द्वारा इसके विरोधाभासी बयान कंपनी की नीति के अनुरूप नहीं है।'' अन्य कई वैश्विक कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने कारोबारी सहयोगियों द्वारा ''कश्मीर एकजुटता दिवस'' के समर्थन में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के लिए माफी मांगी है। इन पोस्ट का भारत में विरोध हुआ और उक्त कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार का भी आह्वान हुआ। इस घटनाक्रम के बाद हुंडै, सुजुकी, टोयोटा, केएफसी और पिज्जा हट ने भी इन पोस्ट के लिए माफी मांगी।

केंद्र ने राज्यों से तिलहनों, तेल पर स्टॉक की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा

नयी दिल्ली(एजेंसी)। खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख था। मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मंत्रालय ने बयान में कहा, ''बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें। लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार में किसी तरह की अड़चन न आने पाए।'' बयान में कहा गया है कि इस कदम से अनुचित व्यवहार मसलन जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी। राज्यों को खाद्य तेलों के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मूल्य परिदृश्य के बारे में भी बताया। राज्यों को इस बात की जानकारी दी गई कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें किस तरह से भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही हैं। खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है। खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है। खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है। थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल, थोक उपभोक्ताओं की खुदरा दुकानों मसलन बड़ी श्रृंखला और रिटेलर के लिए यह सीमा 30 क्विंटल और उनके डिपो के लिए 1,000 क्विंटल है। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिन के बराबर का स्टॉक रख सकते हैं। वहीं तिलहनों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 2,000 क्विंटल है। खाद्य तिलहनों के प्रसंस्करणकर्ता 90 दिन के खाद्य तेलों के उत्पादन के बराबर तिलहनों का स्टॉक रख पाएंगे। इस आदेश के दायरे से निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ बाहर रखा गया है।

सुजुकी मोटर ने भारत में भावनाओं को पहुंची चोट के लिए खेद जताया

नई दिल्ली। जापानी कार कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अपने पाकिस्तानी डीलरों एवं कारोबारी सहयोगियों की तरफ से सोशल मीडिया पर कश्मीर के बारे में की गई टिप्पणियों से भारत में 'भावनाओं को ठेस पहुंचने' पर खेद जताया है। सुजुकी मोटर ने मंगलवार को एक बयान में इस विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना रुख साफ करते हुए कहा, ''इस तरह के असंवेदनशील संचार से भावनाओं को ठेस पहुंचने का हमें गहरा खेद है। हम अपने सभी कारोबारी सहयोगियों को इस संदर्भ में कंपनी की नीति का सख्ती से पालन करने की सलाह देंगे।'' सुजुकी मोटर भारत की सबसे बड़ा कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की मूल कंपनी है। मारुति सुजुकी इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जारी इस बयान में कहा गया कि वह एक भरोसेमंद कंपनी बनना चाहती है और किसी भी राजनीतिक या धार्मिक झुकाव से खुद को नहीं जोड़ती है। पाकिस्तान में सुजुकी के कई डीलरों एवं कारोबारी सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर कश्मीर के साथ जुड़ाव जताने वाले पोस्ट किए हैं। किसी भी राजनीतिक या धार्मिक झुकाव से खुद को नहीं जोड़ती है। पाकिस्तान में सुजुकी के कई डीलरों एवं कारोबारी सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर कश्मीर के साथ जुड़ाव जताने वाले पोस्ट किए हैं।

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 'एक्सिस क्रिसिल एसडीएल 2027 डेट इंडेक्स फंड' लॉन्च किया

मुंबई,। एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो भारत में सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउसों में से एक है, ने अपना नया फंड ऑफर -ज्एक्सिस क्रिसिल एसडीएल 2027 डेट इंडेक्स फंडज् लॉन्च किया। यह एक टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जिसकी बेंचमार्क मैच्योरिटी 31 मई, 2027 है। नया फंड क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल इंडेक्स - मई 2027 को ट्रैक करेगा और पोर्टफोलियो को मुख्य रूप से 01 दिसंबर, 2026 से 31 मई, 2027 के बीच परिपक्व होने वाले स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (एसडीएल) में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूचकांक का प्रबंधन क्रिसिल इंडिसेज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

एसडीएल (स्टेट डेवलपमेंट्स लोन्स) और टार्गेट मैच्योरिटी फंड्स को समझना

एसडीएल राज्य सरकार का डेट है जो बजटीय खर्चों को पूरा करने और विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। एसडीएल सबसे अधिक तरल साधनों में से एक है जो जी-सेक वक्र से ऊपर ट्रेड करता है और इसे लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। इस ट्रेडिंग का प्रबंधन आरबीआई करता है।

टारगेट मैच्योरिटी फंडों को महत्व मिलना शुरू हो गया है क्योंकि उनकी परिभाषित अवधि के कारण निवेशक अवधि रणनीतियों का लाभ उठा सकते हैं। फंड मैनेजर इसे हासिल करने के लिए परिभाषित परिपक्वता तिथि के करीब समान परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और उन्हें परिपक्वता तक रखते हैं। रणनीति का उद्देश्य उन निवेशकों के लिए किसी भी अवधि के जोखिम को नकारना होता है जो फंड की पूरी अवधि के दौरान निवेशित रहते हैं।

एक्सिस क्रिसिल एसडीएल 2027 डेट इंडेक्स फंड

एक्सिस क्रिसिल एसडीएल 2027 डेट इंडेक्स फंड की लक्षित परिपक्वता संरचना बेहतर आवंटन, उच्च गुणवत्ता वाले पैसिव पोर्टफोलियो के निर्माण और उपयुक्त करारोपण में मदद करती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अपेक्षाकृत लंबी निवेश अवधि की तलाश में हैं और जो इंडेक्स की परिपक्वता अवधि के अनुरूप विविध पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोजर प्रदान करना चाहते हैं। यह स्कीम बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करती है जैसा कि अंतर्निहित सूचकांक द्वारा दर्शाया गया है।

एमेज़ॉन ने प्रोपेल स्टार्टअप एक्सलरेटर का सीज़न 2 लॉन्च किया

बैंगलुरू : आज एमेज़ॉन इंडिया ने ग्लोबल सेलिंग प्रॉपेल स्टार्टअप एक्सलरेटर के दूसरे सीज़न के लॉन्च की घोषणा की। यह अभियान उभरते हुए भारतीय ब्रांड एवं स्टार्टअप्स को पूरी दुनिया में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए समर्पित सहयोग देने के लिए डिज़ाईन किया गया है। स्टार्टअप एक्सलरेटर कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स स्पेस में शुरुआती चरण स्टार्टअप्स को सहयोग करने के लिए डिज़ाईन किया गया है, ताकि वो एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम की मदद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर भारत के ग्लोबल ब्रांड्स का निर्माण कर सकें। इसमें भाग लेने वाले स्टार्टअप्स को एमेज़ॉन से 100,000 डॉलर की पूर्णत: ईक्विटी-फ्री ग्रांट जीतने का मौका मिलेगा तथा उन्हें 10,000 डॉलर मूल्य के मुफ्त एडब्लूएस क्रेडिट मिलेंगे। यह प्रोग्राम स्टार्टअप्स को पार्टनर वीसी फर्म्स- एक्सेल, डीएसजी कंज़्यूमर पार्टनर्स, फायरसाईड वेंचर्स एवं सिकोइयाकैपिटल इंडिया को अपने व्यवसायिक प्रस्तावों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। लोकप्रिय बॉलिवुड अभिनेता एवं एंजेल निवेशक, कुणाल कपूर इस प्रोग्राम में मेंटर के रूप में शामिल हो गए हैं।

अमित अग्रवाल, एसवीपी - इंडिया एवं इमर्जिंग मार्केट्स, एमेज़ॉन ने कहा, ''ग्लोबल सेलिंग प्रॉपेल एक्सलरेटर उभरती हुई कंपनियों को अपने व्यवसायिक प्रस्ताव को जीवंत करने एवं भारत में विश्वस्तर पर लोकप्रिय ब्रांड्स का निर्माण करने का अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाईन किया गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश का निर्माण करने तथा स्टार्टअप्स को भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के उद्देश्य के अनुरूप है। प्रोग्राम के पहले सीज़न में हमें बेहतरीन विचार, उत्साह एवं उद्यमशीलता की भावना देखने को मिले, और हम अब सीज़न 2 प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हैं। यह निर्यात को हर आकार के व्यवसाय के लिए आसान बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम 2025 तक भारत से ई-कॉमर्स निर्यात में 10 बिलियन डॉलर का व्यवसाय संभव बनाना चाहते हैं।''

स्टार्टअप एक्सलेरेटर के तहत, एमेज़ॉन ने एक मेंटरशिप बोर्ड का गठन किया है, जिसमें भारत एवं विश्व से एमेज़ॉन लीडर्स, वीसी पार्टनर्स एवं उद्योग के अन्य लीडर्स शामिल हैं, जो उभरते ब्रांडों के साथ जुड़ेंगे और उन्हें अनुरूप संसाधन,1:1 मेंटरशिप एवं विश्व में मांग की संरचना पर कार्यशालाएं तथा ईकॉमर्स द्वारा सफल निर्यात व्यवसाय स्थापित करने की जानकारी प्रदान करेंगे। पहले सीज़न की विजेता, मेघना नारायण, को-फाउंडर, स्लर्प फार्म ने कहा, ''विश्व के बाजारों में विस्तार करने के मिशन के साथ हमने एमेज़ॉन पर कुछ साल पहले स्लर्पफार्म शुरू किया। हम पूरी दुनिया में माताओं को सेवाएं देते हैं और उन्हें अपने बच्चों को पोषणयुक्त भोजन देने में मदद करते हैं, जो बहुत तेजी एवं आसानी से बनाया जा सकता है। एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रॉपेल स्टार्टअप एक्सलरेटर ने पिछले साल हमारी सफलता में मुख्य भूमिका निभाई और हमें एक स्थायी व्यवसायिक मॉडल स्थापित करने में मदद की, जिससे ब्रांड के मूल्य प्रस्ताव और पूरी दुनिया के बाजारों में दृश्यता बढ़े। आज हम अमेरिका और यूके के बाजारों में अपने काम का विस्तार कर चुके हैं और सेल्स में हमें 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि मिल रही है। हमें विश्वास है कि सीज़न 2 ग्लोबल बाजारों में प्रतिभागी स्टार्टअप्स की सफलता सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा।''

बजट में सुधार से रत्न तथा आभूषण उद्योग जगत को बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिलेगी

मुंबई- जीजेईपीसी भारत सरकार और माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में निर्यात वृद्धि उन्मुख केंद्रीय बजट पेश करने के लिए सरकार को अभिनंदन व आभार व्यक्त करता है।

जीजेईपीसी के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा, "भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है और देश डायमंड प्रोसेसिंग में निर्विवाद लीडर है। कट और पॉलिश किए गए डायमंड पर आयात शुल्क को घटाकर 5ब करने से इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने और अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। "

कॉलिन शाह ने आगे बताया कि "सोने के आयात के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर व्यक्तिगत ज़मानत बांड की स्वीकृति, विशेष रूप से सोने के आभूषणों के एसएमई निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त सोने की उपलब्धता को सरल बनाने और प्लेनस्वर्ण आभूषणों के निर्यात को पुनर्जीवित करने की हमारी लंबे समय से मांग को पूरा करेगी। आपूर्तिकर्ताओं के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर ज़मानत बांड को स्वीकार्य बनाया जाएगा। इससे सोने के आभूषणों के निर्यात में मदद मिलेगी।"

जीजेईपीसी के उपाध्यक्ष विपुल शाह ने कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कुछ बहुत आवश्यक सुधारों की घोषणा की है जो आने वाले वर्ष में इस क्षेत्र को कई गुना विकास के लिए प्रेरित करेंगे, इस प्रकार पिछले कुछ दसकों के मामूली प्रदर्शनों में भी सुधार देखने को मिलेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च पर जोर इंडिया ज्वैलरी पार्क मुंबई (आईजेपीएम) के लिए अच्छी खबर है, जिससे इससे काफी फायदा होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इन सुधारों से भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता का स्तर एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा।

नया साल स्टूडेंट्स के लिये लेकर आया बहुप्रतीक्षित अपग्रेड- द युवा स्टेलर

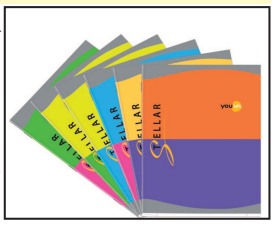

मुंबई- नवनीत हाउस का घरेलू स्टेशनरी ब्रांड युवा, प्रीमियम लॉंग बुक की एक नई सब-कैटेगरी च्युवा स्टेलरज् के लॉन्च के साथ नये साल की शुरूआत करने के लिये पूरी तरह तैयार है। स्टूडेंट्स के लिये लिखने का बेहतरीन अनुभव देने के लक्ष्य के साथ यह एक बेहद जरूरी अपग्रेड है। पिछले कई सालों में मोबाइल, फैशन,ऑटोमोबाइल जैसी कैटेगरी में कई सारे अपग्रेड देखे गये हैं, लेकिन स्टूडेंट लॉंग बुक्स का क्षेत्र अभी तक उपेक्षित था। कॉलेज स्टूडेंट्स लॉंग बुक्स का इस्तेमाल उनके स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस और सवाल-जवाब को रिवाइज करने के लिये करते हैं। यह कॉलेज लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके पास हमेशा रहता है। कई स्टूडेंट्स पेपर की क्वालिटी या फिर लिखने के दौरान स्याही की छाप दूसरे पेज पर पड़ने को लेकर शिकायत करते हैं। युवा ने इस पेशानी को पहचाना और उन स्टूडेंट्स के लिये एक नई सबकैटेगरी तैयार की है, जो पढ़ने के दौरान किसी तरह का भटकाव नहीं चाहते हैं और इसलिये यह अपग्रेड जरूरी है। स्टूडेंट्स के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में उनके प्रगतिशील कदम के रूप में युवा इस अनूठे प्रोडक्ट का लाना चाहता था। समय के साथ ही हर किसी में बदलाव होता है। अपनी जिंदगी, आदतों, पसंद को लगातार अपग्रेड करने की तलब हमेशा रहती है और युवा स्टेलर उसी का एक विस्तार है।

स्टूडेंट्स को खास और आत्मविश्वास महसूस कराने के लिये लेखन अनुभव को बढ़ावा देने के लिये पेपर को स्टाइलिश रूप से डिजाइन किया गया है। मोटे कागज (64 जीएसएम) दूसरी तरफ कोई निशान नहीं छोड़ना सुनिश्चित करेंगे, जिससे उन्हें अपने काम पर एकाग्रता रखने में मदद मिलेगी। यह भी एक सच्चाई है कि मोटे और बेहतर गुणवत्ता वाले कागज पर लिखने से अच्छी लिखावट के साथ लिखने की प्रेरणा मिलती है। स्टेलर लॉंगबुक एक सौम्य और फिनिश्ड मैट लुक प्रदान करते हैं। उनके डिजाइन नये और सरल हैं और फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। किसी भी पहलू से समझौता किये बिना यह एक मजबूत छाप बनाने में मदद करता है। युवा स्टेलर के लॉन्च पर, चीफ स्ट्रैटजी ऑफिसर एवं युवा प्रवक्ता, अभिजीत सान्याल कहते हैं, "किसी के विकास और तरक्की के लिये निरंतर अपग्रेडशन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स किस तरह पढ़ते हैं, उस अनुभव को बेहतर बनाने के लिये लॉंग बुक्स जरूरी है। बाजार में यह कमी साफ नजर आ रही थी और यही वजह थी कि हमने इसकी तरफ रुख किया। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट हैं।

पीसीबी ने रखा विकेटकीपिंग सलाहकार, अब हो रही है आलोचना

कराची । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 73 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी वसीम बारी को यहां अपने हाई परफोर्मेंस सेंटर में विकेटकीपिंग सलाहकार नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आने के बाद पीसीबी को आलोचना का भी सामना करना पड़ा। पीसीबी ने कहा कि उसने बारी के अनुरोध पर और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें विकेटकीपिंग सलाहकार बनाया है। पीसीबी के इस तर्क की पाकिस्तान का क्रिकेट जगत आलोचना कर रहा है। बारी पाकिस्तान क्रिकेट में एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी की है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि वह हाई परफोर्मेंस सेंटर के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनका अनुबंध 31 दिसंबर को समाप्त हो गया और उन्होंने तीन महीने का विस्तार देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने पूर्व कप्तान के सम्मान में, विशेष पद बनाने के लिए कहा था और बारी के लिए तीन महीने के विस्तार को मंजूरी दी। बारी ने पाकिस्तान के लिए 81 टेस्ट और 51 एकदिवसीय मैच खेले हैं। खेल से संन्यास के बाद बारी ने बोर्ड में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। उन्होंने बोर्ड के निदेशक (क्रिकेट संचालन), मुख्य चयनकर्ता, राष्ट्रीय टीम प्रबंधक और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी है।

शतरंज

फीडे ग्रां प्री शतरंज 2022 : विदित नें अरोनियन से खेला ड्रॉ ,प्ले ऑफ की संभावना कायम

बर्लिन,जर्मनी।

फीडे ग्रां प्री सीरीज के पहले पड़ाव बर्लिन ग्रां प्री मे पूल डी में खेल रहे भारत के विदित गुजराती नें चौंथे राउंड मे सबसे आगे चल रहे यूएसए के लेवोन अरोनियन के खिलाफ एक रोचक बाजी खेली पर अरोनियन अपने अनुभव से बिना किसी मुश्किल के मैच ड्रॉ करने मे सफल रहे । सफ़ेद मोहरो से खेल रहे विदित नें इंग्लिश ओपनिंग मे 1967 में खेले गए एक मुक़ाबले की तर्ज पर खेल की 11वीं चाल में अपने प्यादे की कुर्बानी देकर मैच में अरोनियन को मुश्किल में डालने की कोशिश की पर अरोनियन सही बचाव करते हुए 32 चालों मे खेल ड्रॉ कराने मे सफल रहे और 3 अंको के साथ शीर्ष पर बने हुए है ,पूल डी के दूसरे मुक़ाबले में रूस के डेनियल डुबोव नें जर्मनी के विन्सेंट केमर को मात देते हुए अपनी पहली जीत हासिल की । पूल डी में यूएसए के वेसली सो नें हमवतन लिनियर दोमिंगेज को मात देते हुए 3.5 अंको के साथ एकल बढ़त कायम रखी है जबकि भारत के पेंटाला हरिकृष्णा स्पेन के अलेक्सी शिरोव से ड्रॉ खेलकर दूसरे स्थान पर बने हुए है । पूल ए में रूस के आन्द्रे एसेपिंकों नें हमवतन अलेक्ज़ेंडर ग्रीसचुक से ,फ्रांस के ऐटेने बकरोट नें यूएसए के हिकारु नाकामुरा से बाजी ड्रॉ खेली और यहाँ 2.5 अंक बनाकर नाकामुरा की बढ़त बरकरार ह पूल ए में रूस के आन्द्रे एसेपिंकों नें हमवतन अलेक्ज़ेंडर ग्रीसचुक से ,फ्रांस के ऐटेने बकरोट नें यूएसए के हिकारु नाकामुरा से बाजी ड्रॉ खेली और यहाँ 2.5 अंक बनाकर नाकामुरा की बढ़त बरकरार है ।

वहीं पूल बी में मे रूस के ब्लादिमीर फेडोसीव नें हमवतन ओपरिन ग्रीग्रोय को पराजित किया जबकि पोलैंड के रडास्लाव वोइटसजेक और हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट के बीच बाजी ड्रॉ रही और यहाँ फिलहाल फेडोसीव और वोइटसजेक 2.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रहे है । छह राउंड के बाद हर पूल के शीर्ष खिलाड़ी सीधे सेमी फाइनल मे प्रवेश कर जाएँगे ।

रणजी ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने जारी किए नियम, एक टीम 20 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं रख सकती

नई दिल्ली ।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फैसला किया है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम में 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और टीम में कम से कम 20 खिलाड़ी होने चाहिए। इसके साथ ही सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों की संख्या को 10 तक सीमित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी टीमों को दो रिजर्व खिलाड़ी रखने की अनुमति भी दी है। बीसीसीआई ने 17 फरवरी से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट से पहले मंगलवार को सभी राज्य क्रिकेट संघों को इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने ईमेल के जरिए सभी संघों को लिखे पत्र में कहा कि सभी टीमों को कोविड रिजर्व के तौर पर दो अतिरिक्त खिलाड़ियों को टीम के साथ रखने की अनुमति दी जाती है। वहीं अगर कोई भारतीय टीम का सदस्य इस टूर्नामेंट में भाग लेता है तो वह मैचों में अपनी प्लेइंग इलेवन और नॉन-प्लेइंग इलेवन की स्थिति के आधार पर 20 खिलाड़ियों से अधिक मैच फीस का पात्र होगा। टूर्नामेंट में मैच फीस का भुगतान कैसे किया जा सकता है, बीसीसीआइ ने इस पर एक सामान्य एडवाइजरी भी जारी की है। बोर्ड के मुताबिक 20 खिलाड़ियों में से प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी 2.4 लाख रुपए की पूरी मैच फीस के हकदार होंगे, जबकि शेष 9 खिलाड़ियों को इसका 50 प्रतिशत मिलेगा। बीसीसीआई ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रत्येक टीम के लिए रिपोर्टिंग की तारीख 10 फरवरी है। इसी दिन से टीम पांच दिवसीय क्वारंटीन शुरू करेगी जो 14 फरवरी को समाप्त होगा। दो दिनों के अभ्यास के बाद पहले दौर के मैच 17 फरवरी से शुरू होंगे। देश भर के 9 केंद्र कटक, राजकोट, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, हरियाणा, गुवाहाटी और कोलकाता इस दो चरणों वाले टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी करेंगे। बीसीसीआई के मुताबिक प्रत्येक टीम को तीन लीग मैचों की अनुमति है और पहला चरण एलीट डिवीजन में सबसे कम रैंक वाली टीम और प्लेट में सर्वोच्च रैंक वाली टीम के बीच प्री-क्वार्टर फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा। प्री-क्वार्टर फाइनल 12 से 16 मार्च तक होंगे ।

हार्दिक पांड्या की टीम ने किया अपने नए नाम का ऐलान

नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया है. उन्हें आईपीएल से नई जुड़ी टीम अहमदाबाद ने अपने साथ जोड़ा है. अब अहमदाबाद टीम ने अपने नए नाम का ऐलान किया है. आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि दर्शकों को 10 टीमें खेलते हुए दिखाई देंगी. आईपीएल में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है यहां लोगों को रोमांच, उत्साह और तनाव अपने चरम सीमा पर देखने को मिलता है. आईपीएल में हर टीम का एक अलग नाम होता है. अब आईपीएल से नई जुड़ी अहमदाबाद टीम ने अपने नाम की घोषणा की है, जिसका सभी को इंतजार था. अहमदाबाद टीम अपने एक खास नाम के साथ आईपीएल 2022 में उतरने वाली है. में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली अहमदाबाद की टीम अहमदाबाद टाइटंस के नाम से जानी जाएगी. अहमदाबाद का मालिकाना हक सीवीसी कैपिटल के पास है, उन्होंने 5625 करोड़ रुपये में खरीदा है. अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से टीम का नया नाम सामने आया है. अहमदाबाद टीम ने तीन प्लेयर्स अपने साथ जोड़े हैं, उन्होंने अपने कप्तान की घोषणा कर दी है. हार्दिक पांड्या अहमदाबाद टीम के कप्तान होंगे. हार्दिक बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर हैं. उन्होंने आईपीएल में ढेरों रन कूटे हैं. वह डेथ ओवर्स में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं. दूसरे खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान और तीसरे खिलाड़ी के तौर पर स्टार ओपनर शुभमन गिल को अपने साथ जोड़ा है। 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे गैरी कर्स्टन को अहमदाबाद ने अपना मेंटर बनाया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा टीम के मुख्य कोच और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी टीम के डायरेक्टर हैं.

वित्तीय अनुदान : राज्य चाहते हैं कि एआईएफएफ बीसीसीआई से सबक ले

नई दिल्ली ।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के सदस्य संघों ने राज्य इकाइयों को वित्तीय मदद देने के मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का अनुसरण करने की मांग की। एआईएफएफ की शनिवार को मुंबई में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान सदस्य संघों द्वारा दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का उदाहरण दिया गया था। महासंघ के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि कुछ सदस्यों ने वित्तीय सहायता के मामले में राज्य संघों को बीसीसीआई के समर्थन का उदाहरण दिया। उन्होंने एआईएफएफ से अपने संबंधित राज्यों में फुटबॉल के विकास को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन के साथ मदद करने का आग्रह किया। एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मामले की 'निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने संघों से एक बेहतर कामकाजी संबंध बनाने और अपनी संबंधित राज्य सरकारों से समर्थन लेने का भी आग्रह किया। पटेल ने फुटबॉल के विकास के लिए ओडिशा, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों के समर्थन की ओर भी इशारा किया। उन्होंने एजीएम के दौरान कहा कि एआईएफएफ राज्य संघों को वित्तीय अनुदान मंजूर करेगा। उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 महामारी की असाधारण

परिस्थितियों में पिछले साल कोष की पेशकश की थी। हम इस साल फिर से राज्य संघों के साथ खड़े होने के लिए अपने बजट पर काम करेंगे। इस बीच, यह पता चला है कि कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघ (केएसएफए) के अध्यक्ष एनए हैरिस चाहते थे कि पारित करे जो पटेल को एआईएफएफ प्रमुख के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए जारी रखने की अनुमति दे। एजीएम एक विशेष प्रस्ताव पारित करे जो पटेल को एआईएफएफ प्रमुख के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए जारी रखने की अनुमति दे। इस सुझाव को हालांकि तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि यह खेल संहिता का उल्लंघन है।

संक्षिप्त समाचार

बेबी एबी डिविलियर्स कहे जाने पर डेवाल्ड ब्रेविस बोले - यह बहुत बड़ा सम्मान है

जोहान्सबर्ग । दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा है कि बेबी एबी डिविलियर्स कहलाना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अंडर-19 विश्व कप में ब्रेविस के शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी दिग्गज एबी डिविलियर्स के साथ तुलना की गई। उनके स्टाइल और क्लास की वजह से उन्हें बेबी एबी कहा जा रहा है, जिसे लेकर वह बेहद खुश भी हैं। बेबी एबी कहे जाने पर ब्रेविसो ने कहा कि मुझे यह भी नहीं पता कि क्या कहना है। मैं एबी डिविलियर्स के आस-पास कहीं नहीं हूं। वह एक ऐसा लड़का है जिसे मैं आदर्श मानता हूं, वह पहली बार क्रिकेट देखने के बाद से मेरा आदर्श है। ब्रेविस ने कहा, मुझे यह पसंद है कि यह एक वास्तविक सम्मान और असली बात है। सेंचुरियन-आधारित फ्रैंचाइजी के लिए अनुबंधित खिलाड़ी के रूप में अपने पहले सीजन में ब्रेविस ने विश्व कप में आश्चर्यजनक रूप से 506 रन बनाए जो एक टूर्नामेंट में कई क्रिकेट दिग्गजों के करियर को आगे ले जाने के लिए पर्याय है।क्विंटन डी कॉक, कैगिसो रबाडा और एडेन मार्कराम सभी ने वर्षों से टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अन्य वैश्विक सुपरस्टार जैसे ब्रायन लारा, इंजमाम-उल-हक, सनथ जयसूर्या और विराट कोहली ने भी अपने लिए एक नाम बनाया। ब्रेविस ने कहा, मैंने जो किया उसे पूरा करना बहुत बड़ा सम्मान था। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और मेरा मानना है कि साधारण चीजों को सही करने से सभी फर्क पड़ता है। इससे हमने जिन परिस्थितियों का सामना किया और जिन टीमों का सामना किया, उनमें बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में विनम्र था क्योंकि आप इन सभी लोगों के नाम देखते हैं जो वर्षों से अंडर 19 विश्व कप में गए हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आप बड़े हुए हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के महान खिलाड़ी बन गए हैं। वे वर्षों तक क्रिकेट में हावी थे और उनके बीच आपका नाम सुनना अविश्वसनीय है। यह मेरे लिए उसी तरह जारी रखने के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

100 साल के हुए दुनिया के सबसे बुजुर्ग शतरंज ग्रांड मास्टर अवेरबख

मॉस्को । विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित शतरंज ग्रांड मास्टर यूरी अवेरबख नें कल अपना 100वां जन्मदिन मनाया । विश्व शतरंज संघ ने उन्हे शुभकामना देते हुए उनके शतरंज को दिये गए योगदान के लिए याद किया । यूरी अवेरबख का जन्म रूस के कालूगा में 8 फरबरी 1922 को हुआ था । शतरंज में उन्हे विश्व चैम्पियन मेक्स एवुए को 1953 के दो लगातार मुकाबलों में पराजित करने के लिए भी जाना जाता है इसके अलावा उनकी शतरंज पर लिखी किताबे पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है खासतौर पर एंडगेम में उनकी महारत काबिले तारीफ रही है । यूरी 86 साल की उम्र तक क्लासिकल शतरंज खेलते रहे और उनका आखिरी मैच उन्होने 2008 में खेला था । वो अब भी कभी कभार युवा खिलाड़ियों को सलाह देते नजर आते है । यूरी सोवियत यूनियन शतरंज विजेता होने के साथ साथ विश्व शतरंज संघ मे कई पदो पर रहे ।

जुड़वां बच्चों की मां बनी दीपिका चार साल बाद स्क्वाश कोर्ट पर करेंगी वापसी

नई दिल्ली ।

भारत की बेहतरीन स्क्वाश खिलाड़ियों में से एक दीपिका पल्लीकल ने परिवार बढ़ाने के लिए ब्रेक लेने के चार साल बाद कोर्ट पर वापसी की है। पिछले साल जुड़वां बच्चों की मां बनी दीपिका इस साल के अंत में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों पर ध्यान लगाने के लिए पिछले दो महीनों से कड़ी ट्रेनिंग में जुटी हैं। खेल के दूर रहने के दौरान 31 साल की दीपिका ने 'इंटीरियर डिजाइनिंग% में हाथ आजमाया। पर अब वह इन कई स्पर्धाओं वाली दो खेल प्रतियोगिताओं में इतिहास रचने पर नजर लगाए हैं। उनके बर्मिंघम खेलों में युगल स्पर्धा में भाग लेने की उम्मीद है जिसक बाद वह अपना कार्यभार धीरे-धीरे बढ़ाएंगी और हांगजोऊ खेलों में एकल स्पर्धा भी खेलेंगी। पल्लीकल और भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में खेला का पहला स्वर्ण पदक 2014 ग्लास्गो चरण में जीता था। मां बनने और वापसी के बारे में बात करते हुए पल्लीकल ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि उन्हें पास सहयोग के लिए लोग मौजूद थे जिससे उन्हें 2018 में खेल से थोड़े समय तक दूर रह सकीं। जब उन्होंने ब्रेक लिया था तो वह शीर्ष 20 में शामिल थी। दो बच्चों की मां बनना 'दोहरी मेहनत है लेकिन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी पल्लीकल अपनी जिंदगी के इस दौर का लुत्फ उठा रही हैं। उन्होंने कहा, 'हां, एक मां और पेशेवर एथलीट बनना मुश्किल है। लेकिन मैं इस पर जोर नहीं देना चाहती। निश्चित रूप से बच्चों के सोने के समय के चक्र के साथ काफी मुश्किल होती है और जुड़वां बच्चों के कारण यह दोगुनी मेहनत है।

उन्होंने कहा, 'मेरे पति भी एथलीट हैं और वह अभ्यास और खेलने के लिए बाहर रहते हैं। इसलिए काफी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे परिवार के रूप में मेरे पास सहयोग के लिए मजबूत प्रणाली मौजूद है जिससे मुझे सुबह और शाम में अभ्यास करने के लिए समय मिल जाता है। पिछले साल घुटने की चोट और महामारी के कारण उनकी वापसी में विलंब हुआ। वह प्रतिस्पर्धी वापसी जोशना के साथ अप्रैल में ग्लास्गो में होने वाली महिला युगल विश्व चैम्पियनशिप में कर सकती हैं। चेन्नई की इस खिलाड़ी की योजना है कि वह एशियाई खेलों के बाद ही पीएसए पेशेवर टूर में वापसी करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि एक और महीने के अभ्यास के बाद वह पूरी तरह से वापसी के लिये तैयार होंगी। पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से नवाजी जा चुकी पल्लीकल का दो बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन ट्रायल्स में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

दूसरे वनडे में ऋषभ पंत और केएल राहुल ने बनाए रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क । भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आई। पहले बल्लेबाजी के लिए आई भारतीय टीम की ओर से दो बल्लेबाजों ने इस मैच में रिकॉर्ड बनाए हैं। इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए ऋषभ पंत ने अपने

करियर में 3 हजार रन पूरे कर लिए हैं जबकि केएल राहुल ने भी अपने करियर में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं। इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारत के लिए पहली बार बतौर सलामी बल्लेबाज आए। सलामी बल्लेबाजी के तौर पर आए पंत इस मैच में कुछ ज्यादा खास कर तो नहीं पाए पर उन्होंने अपनी 18 रन की पारी के दौरान क्रिकेट करियर में 3 हजार रन पूरे कर लिए। पंत ने इस मैच में 34 गेंदों पर 3 चौकों की मदद वहीं इस मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल अच्छी लय में दिख रहे थे। केएल राहुल ने शुरूआती विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी को संभाला। पर सूर्यकुमार के साथ ताल-मेल की कमी कारण वह रन आउट हो गए। केएल राहुल ने 48 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 49 रन बनाए। इस पारी के साथ केएल राहुल ने अपने करियर में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं। साथ केएल राहुल ने अपने करियर में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं। गौर हो कि भारत और वेस्टइंडीडज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात दी थी। वहीं भारत दूसरे मैच को भी जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगा।

बीसीसीआई ने दूसरे वनडे मैच में अंडर-19 विश्वकप विजेता टीम को किया सम्मानित

अहमदाबाद । भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम को बुधवार को यहां दूसरे वनडे के मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा सम्मानित किया गया। अंडर-19 टीम के नायक ब्लेजर पहने थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्टैंड से भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच देखा। उन्होंने मुख्य कोच ऋषिकेश कानिटकर व सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अपने स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा और खेल का आनंद लिया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भी इस मौके पर मौजूद थे। लक्ष्मण टीम के साथ वेस्टइंडीज में थे। साथ ही बीसीसीआई सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरूण धूमल के साथ राज्य क्रिकेट संघ के कुछ सीनियर अधिकारी भी स्टेडियम में उपस्थित थे।

एंडरसन और ब्रॉड को टीम से बाहर करने पर मुख्य चयनकर्ता स्ट्रॉस ने दिया बयान

लंदन ।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन की भड़ास अब टीम प्रबंधन से ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गई है। इसके चलते टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले अनुभवी तेज गेंदबाजों जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को आगामी वेस्ट इंडीज दौरे से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के अंतरिम क्रिकेट निदेशक एंड्रयू स्ट्रॉस ने हालांकि कहा है कि इस निर्णय का मतलब यह नहीं है कि यह दोनों खिलाड़ियों के करियर का अंत है। स्ट्रॉस ने कहा कि नए चयनकर्ता ने टेस्ट कप्तान जो रूट से जानकारी ली थी और वह ऑस्ट्रेलिया में मिली हार के कारण एक सीमा रेखा खींचना चाहते थे। अनुभवी जोड़ी के दीर्घकालिक भविष्य के बारे में फैसला करना स्थायी प्रबंध निदेशक और मुख्य कोच पर निर्भर करेगा। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के संबंध में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के रूप में यह उनके करियर का अंत नहीं है। स्ट्रॉस ने कहा कि हमें लगता है कि कुछ रोमांचक नई गेंदबाजी क्षमता को देखना और अन्य खिलाड़ियों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देना महत्वपूर्ण है जो पहले खेल चुके हैं। एंडरसन और ब्रॉड इंग्लैंड के सेट-अप में जो गुणवत्ता और अनुभव लाते हैं, उस पर किसी को संदेह नहीं है। यह नए प्रबंध निदेशक और स्थायी मुख्य कोच पर निर्भर करेगा कि वे इस गर्मी और उसके बाद टीम में शामिल होंगे या नहीं। इस टीम का यह चयन एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है और इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को वहां वापस लाने के लिए एक यात्रा है, जहां इसे होना चाहिए और अब कड़ी मेहनत शुरू होगी। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम : जो रूट (कप्तान), जैक क्रॉली, ओली पोप, साकिब महमूद, एलेक्स लीज, बेन फोक्स (विकेटकीपर), मार्क वुड, क्रिस वोक्स, मैथ्यू पार्किंसन, जॉनी बेयरस्टो, ऑली रॉबिन्सन, मैथ्यू फिशर, डैन लॉरेंस, क्रेग ओवटर्न, जैक लीच, बेन स्टोक्स।

रोहित के लिए सिरदर्द बने विराट, 3 नंबर पर इस खतरनाक बल्लेबाज को जगह देंगे कप्तान!

नई दिल्ली। टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज का सामना कर रही है. इस सीरीज के पहले मैच को जीतने के बाद भारतीय टीम पहले से तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. दूसरे मैच में टॉस हारकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मैच में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और कप्तान रोहित शर्मा समेत भारत के पहले तीन विकेट 12 ओवरों में ही गिर गए. आउट होने वाले बल्लेबाजों में एक नाम दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का भी था. विराट की खराब फॉर्म टीम में उनकी जगह के लिए मुसीबत बन चुकी है.। विराट कोहली की फॉर्म पिछले कुछ मैचों से ज्यादा खास नहीं रही. ये बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में पिछले दो सालों से कोई शतक भी नहीं लगा पाया है. साउथ अफ्रीका दौरे पर फ्लॉप रहने वाले विराट वेस्टइंडीज सीरीज में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं. विराट पहले मैच में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं दूसरे मुकाबले में इस बल्लेबाज के पास शतक लगाने का अच्छा मौका था, लेकिन वो सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में उनकी जगह को अब टीम में बड़ा खतरा जरूर है. अगर विराट कोहली को खराब फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप किया जाता है तो इस वक्त दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं. जी हां, इन खिलाड़ियों का नाम सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन है. ये दोनों ही खिलाड़ी भारत का भविष्य हैं और आने वाले समय में विराट की जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। अगर विराट को ड्रॉप नहीं भी किया जाता तो तीन नंबर से हटाकर उन्हें नीचे किसी स्थान पर बल्लेबाजी दी जा सकती है. सूर्यकुमार ने अबतक मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की है ।

चिंतन शिविर का सामूहिक चिंतन जनहितकारी और सुशासन की सच्ची दिशा हैः मुख्यमंत्री

अहमदाबाद । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि चिंतन शिविर के माध्यम से होने वाले सामूहिक चिंतन और मनन से जो नवनीत निकलता है वह लोकहितकारी और सुशासन की सच्ची दिशा है। बुधवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) में राज्य के सहकारिता विभाग के दो दिवसीय चिंतन शिविर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस चिंतन शिविर में राज्य के जिला सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए चिंतन शिविर के सफल दृष्टिकोण में हमें और तेजी लानी है। उन्होंने कहा कि समान हित के लिए एक समान ध्येय के साथ 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र के आधार पर सहकारिता क्षेत्र विकास का अनोखा मॉडल बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी नजदीक से छूने वाला क्षेत्र है। यही नहीं, किसान, उद्यमी महिलाएं और छोटे व्यवसायियों के लिए इस क्षेत्र में सफलता के अनेक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि सहकारी क्षेत्र में 'रिडिफाइन, रिइन्वेंट और रिफॉर्म' की प्रधानमंत्री की संकल्पना को साकार करने के लिए गुजरात का सहकारिता विभाग तैयार है। इस संदर्भ में उन्होंने विभाग की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन बनाने, वेब पोर्टल और स्मार्ट फोन एप्लीकेशन की सुविधा विकसित करने की दिशा में सामूहिक मंथन की जरूरत पर रोशनी डाली। मुख्यमंत्री ने वर्तमान कोरोना काल के बाद की स्थिति में आत्मनिर्भरता के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना' या 'गुजरात आत्मनिर्भर सहाय योजना' के व्यापक कार्यान्वयन में 'उत्प्रेरक एजेंट' बनने का अधिकारियों से आह्वान किया। पटेल ने उम्मीद जताई कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसान सहकारी समितियों को विशेष रूप से प्रेरित करने की दिशा में भी सहकारिता विभाग कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग का गठन किया गया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री भी गुजरात के सपूत श्री अमित शाह हैं, तब राज्य का सहकारिता विभाग केंद्र के साथ समन्वय बनाकर देश में सहकारिता क्षेत्र का विशिष्ट मॉडल बनेगा। पटेल ने कहा कि यह चिंतन शिविर केवल एक कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि आने वाले दिनों में सहकारिता विभाग की नई जनहितकारी और सहयोगी कार्य प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने वाला रोड मैप बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के वेब पोर्टल को लॉन्च किया। उद्घाटन अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, राज्य मंत्री मुकेश पटेल और जीतूभाई चौधरी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन और सहकारिता विभाग के सचिव नलिन उपाध्याय मौजूद थे।

प्रमुख बिजनेस मैगजीन ने सूरत की मेहता वेल्थ लिमिटेड को कंपनी ऑफ द ईयर से किया सम्मानित

सूरत स्थित मेहता वेल्थ लिमिटेड, जो पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट में माहिर है, को बिजनेस कनेक्ट मैगजीन द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है।

2005 में स्थापित, एचएनआई के लिए अनुकूलित निवेशक पोर्टफोलियो की पेशकश करने वाली कंपनी को सिलिकॉन इंडिया, द सीईओ स्टोरी और द बिजनेस फेम जैसी लोकप्रिय व्यावसायिक पत्रिकाओं में भी व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। उन्होंने इससे पहले मुंबईमें ईटी नाउ वर्ल्ड बीएफएसआई कांग्रेस एंड अवार्ड में 101 सबसे प्रभावशाली बीएफएसआई लीडर्स अवार्ड जीता है। एक कंपनी जो न केवल सेल्स करती है, बल्कि एक रिश्तों की शुरुआत करती है। कंपनी केयूर मेहता - (अध्यक्ष और सीआईओ), कुणाल मेहता - (एमडी और सीईओ), किंजल मेहता - (निदेशक और सीओओ) की तिकड़ी द्वारा संचालित है। जिनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता ट्रेडमार्क हैं।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को 11 फरवरी को कोर्ट सुनाएगी सजा

अहमदाबाद। यहां की विशेष अदालत 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को 11 फरवरी को सजा सुनाएगी। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 77 आरोपियों में से 28 को सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषित किया था, जबकि 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज यानी बुधवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन अब इसका ऐलान 11 फरवरी को किया जाएगा। आज सुबह सभी दोषियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था और दोनों पक्षों के बीच दलील भी हुई। बचाव पक्ष ने सजा का ऐलान तीन सप्ताह बाद करने की पेशकश की है। बचाव पक्ष की दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसा कोई प्रावधान है तो बताइए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि दोषियों को सुधरने के अवकाश दिया जाना चाहिए। दोषियों की शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक स्थिति और मेडिकल प्रमाण पेश करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष की दलील पर सरकारी वकील ने कहा कि दोषियों ने एक जघन्य अपराध किया है और उन्हें अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। सरकारी वकील की ओर से अदालत में राजीव गांधी हत्या केस में कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि वाल्मिकी जैसे लोग रोज नहीं पैदा होते, जिनमें सुधार का अवकाश का हो। दोषियों के आपराधिक इतिहास, सुरंग कांड जैसी घटनाओं का कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से कहा कि वे आज ही जेल में बंद दोषियों से मुलाकात करें और उनका पक्ष जानकर उसे अदालत के समक्ष पेश करें। साथ ही कोर्ट ने जयपुर, बेंगलुरू, गया, भोपाल और अन्य जेलों में बंद कैदियों की मेडिकल डिटेइल और अन्य दस्तावेज आज शाम तक साबरमती सेंट्रल भेजने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 11 फरवरी को दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है 26 फरवरी 2008 को अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 56 जितने निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। मंगलवार को इस मामले में गिरफ्तार 77 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया था। जबकि 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषत किया था। हांलाकि निर्दोष घोषित 28 में से 22 आरोपियों को फिलहाल जेल से रिहा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य राज्यों में भी मुकद्दमे चल रहे हैं।

अहमदाबाद इकाई ने राजकोट मंडल के राजकोट-ओखा खंड को चालू करके एक और उपलब्धि हासिल की

अहमदाबाद । भारतीय रेलवे के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के क्रम में, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, अहमदाबाद इकाई ने राजकोट मंडल के राजकोट-ओखा खंड को चालू करके एक और उपलब्धि हासिल की है। रेलवे विद्युतीकरण/अहमदाबाद के मुख्य परियोजना निदेशक श्री ए के चौधरी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिससे नए विद्युतीकृत खंड में माल और यात्री ट्रेन के परिचालन में सुविधा होगी। सीआरएस निरीक्षण के पूर्व खंड का विद्युत लोको परीक्षण 110 किमी प्रति घंटे की गति से सफलतापूर्वक दो बार पूरा किया गया है। श्री आर के शर्मा, सीआरएस/डब्ल्यूसी ने 09.02.2022 को 70 आरकेएम और 87 टीकेएम के भाटिया-ओखा सेक्शन का निरीक्षण किया और ओएचई सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा में तकनीकी पहलू और सुधार के लिए सलाह दी। प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता पश्चिम रेलवे, श्री जी एस भवरिया के साथ मुख्यालय / पश्चिम रेलवे के अधिकारियों और मंडल रेल प्रबंधक राजकोट, श्री ए के जैन के एवं राजकोट मंडल के अधिकारियों के साथ सेक्शन का सीआरएस निरीक्षण किया। यह कमीशनिंग होने से, राजकोट के ओखा से द्वारका के माध्यम से मिसिंग लिंक को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है द्वारका एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहां प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, जिसमें मुख्य मंदिर, नक्काशीदार प्रवेश द्वार और भगवान कृष्ण की काले संगमरमर की मूर्ति के स्थित है।

यह विद्युतीकृत खंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ तेज और बेहतर ट्रेन सेवा का कार्य करेगा, जो भारतीय रेलवे पर नवीनतम हरित पहल के रूप में हरित भारत के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देगा। रेलवे विद्युतीकरण के शीघ्र पूरा होने का लाभ बहुत प्रभावशाली है जो डीजल लोकोमोटिव की निर्भरता को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और इससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जो ईंधन के आयात के कारण वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता करेगा। रेलवे विद्युतीकरण टीम अहमदाबाद द्वारा भाटिया से ओखा तक की इस परियोजना के विद्युतीकृत करने में, विद्युत, सिविल तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों को करने में लगभग 103 करोड़ रुपये की लागत आई है।

गुजरात में कोरोना के 2560 नए मरीज मिले, 8812 लोग हुए ठीक, 24 मरीजों की मौत

अहमदाबाद। बुधवार का राज्य में कोरोना के 2560 नए मामले सामने आए, वहीं 88 12 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि 24 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। बुधवार को राज्यभर में 1.3। लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद में सबसे अधिक 965 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए। वडोदरा कॉर्पोरेशन में 296, वडोदरा में 110, मेहसाणा में 106, बनासकांठा में 100, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 97, राजकोट कॉर्पोरेशन में 83, सूरत में 82, सूरत कॉर्पोरेशन में 79, कच्छ में 73, राजकोट में 51, आणंद में 42, खेडा में 42, गांधीनगर में 38, पाटन में 36, भावनगर कॉर्पोरेशन में 35, भरुच में 29, मोरबी में 29, पंचमहल में 28, साबरकांठा में 23, नवसारी में 22, अहमदाबाद में 21, तापी में 21, दाहोद में 17, वलसाड में 15, डांग में 14, देवभूमि द्वारका में 14, गिर सोमनाथ में 12, अरवल्ली में 11, छोटाउदेपुर में 11, सुरेन्द्रनगर में 10, अमरेली में 9, जामनगर कॉर्पोरेशन में 9, भावनगर में 7, महीसागर में 5, नर्मदा में 5, जूनागढ़ में 4, बोटाद में 3, जामनगर में 3, जूनागढ़ कॉर्पोरेशन में 2 और पोरबंदर में 1 समेत राज्यभर में कोरोना के कुल 2560 संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। जबकि कोरोना से 24 मरीजों की मौत के साथ राज्य में इस रोग से मरनेवालों की संख्या 10740 हो गई है। वहीं 8812 लोगों के डिस्चार्ज किए जाने के साथ राज्य में अब तक कुल 1170117 नागरिक कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 2 1355 सक्रिय मरीजों में 2718 4 स्टेबल हैं और 171 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं। आज राज्य में 137094 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। जिसमें 22 हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को पहला और 568 को दूसरा डोज दिया

गया। 45 वर्ष से अधिक आयु के 4422 को पहला और 456 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया। 18 से 45 वर्षीय 17129 लोगों को कोविड की पहली और 36014 लोगों को दूसरी वैक्सीन दी गई। 15 से 18 वर्षीय 11887 किशोरों को पहला और 34-212 कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया। जबकि 32384 नागरिकों को बूस्टर डोज दिया गया। राज्य में अब तक कुल 10 करोड़ 3 लाख 43 हजार 811 नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा चुका है।

तांत्रिक के दुष्कर्म की शिकार कोरोना संक्रमित महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

छोटाउदेपुर। जिले के संखेडा क्षेत्र में तांत्रिक द्वारा कोरोना संक्रमित विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस तक मामला तब पहुंचा जब पीड़ित महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कानूनी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक छोटाउदेपुर जिले के संखेडा में रहनेवाली 33 वर्षीय महिला के पति की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई थी। पिछले महीने उत्तरायण के दौरान महिला भी कोरोना संक्रमित हो गई। डॉक्टरों ने महिला को कोरंटाइन होने की सलाद दी। इसका महिला के पति के तांत्रिक दोस्त लालाकालूभाई परमार को चला तो वह उसके पास पहुंच गया। तांत्रिक ने महिला से कहा कि यदि घर में रहेगी तो परिवार के अन्य लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। बेहतर होगा कि वह उसके घर चले और ऊपरी मंझिल के खाली कमरे में कोरंटाइन हो सकती है। घर जैसे संबंध होने के कारण महिला ने तांत्रिक पर भरोसा कर लिया और वह उसके घर चली गई। जहां दो दिन के बाद तांत्रिक लाला अपने घर की ऊपरी मंझिल पर जहां महिला रुकी थी वहां पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद तांत्रिक ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वह जान से मार देगा। साथ उसके साथ शादी नहीं करने पर परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। महिला का कोरन्टाइन पूर्ण होने पर तांत्रिक के साथी पिन्टू राठवा गाडी में उसे लेकर मंदिर पहुंच गया। जहां तांत्रिक के साथ उसकी पत्नी के आवा सुखराम राठवा, नरसिंह राठवा, पिन्टू सुंदर, संजु पटेल इत्यादि ने महिला पर शादी करने का दबाव बनाया। जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया और उसके आधार पर तांत्रिक समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की।

कोर्ट ने नवलखी सामूहिक दुष्कर्म केस में दोनों दोषियों को सुनाई ताउम्र कैद की सजा

वडोदरा । वडोदरा के पोक्सो कोर्ट ने शहर के नवलखी सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही रु. 50000 का जुर्माना भी किया है। सरकारी वकील ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। करीब 26 महीने पुराने इस मामले पर नजर डालें तो 28 नवंबर 2019 को 14.8 वर्षीय किशोरी अपने मंगेतर के साथ वडोदरा के नवलखी ग्राउंड में बैठी थी। उस वक्त किशन माथासुरिया और जशा सोलंकी नामक दो शख्स उनके पास पहुंच गए। किशन और जशा ने किशोरी के मंगेतर को डरा-धमका कर वहां से भगा दिया और उसके बाद किशोरी को निकट की झाड़ी में घसीट ले गए। जहां दोनों ने किशोरों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने 45 दिनों में जांच पूर्ण कर पोक्सो कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी। पुलिस ने इस मामले में 40 गवाहों की जांच की थी। पीड़ित समेत दो लोगों का 164 के तहत बयान कलमबद्ध किया गया था। अहमदाबाद और वडोदरा क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच की थी। मामले की पैरवी के लिए खास सरकारी वकील प्रवीण ठक्कर को नियुक्त किया गया और इसकी सुनवाई भी फास्ट ट्रेक कोर्ट में की गई। बुधवार को पोक्सो कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आरोपियों को पेश किया गया। सरकारी वकील प्रवीण ठक्कर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सायन्टिफिक प्रमाण मिले हैं और डीएनए मैचिंग समेत मजबूत सबूतों का हवाला देते हुए दोनों आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की। करीब 26 महीने चले मुकद्दमे के आज फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोनों को पोक्सो की धारा 6/1 के तहत दोषी करार देते हुए ताउम्र कैद की सजा का आदेश दिया। साथ ही रु. 50000 के जुर्माने का भी आदेश दिया है।

महाराष्ट्र में लूट के तीन मामलों में वान्टेड आरोपी सूरत के पलसाणा से पिस्टल लेकर गिरफ्तार

सूरत। सूरत जिला एलसीबी के अनुसार, आरोपी को महाराष्ट्र में विभिन्न अपराधों में रंगेहाथ पकड़ा गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह धूलिया जिले के अलग-अलग थानों में लूट की तीन वारदातों में वान्टेड था। आरोपी के पास से एक बनावटी पिस्टल भी बरामद हुई है।

पिस्टल लेकर वह आदमी जोलवा, पलसाणा व बगुमारा क्षेत्र में घुम रहा था। जिला एलसीबी पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ गफूर और दीपक भाई, अनिलभाई को सूचित किया गया कि कबीर सोनवणे नाम का एक आरोपी, जो महाराष्ट्र के धूलिया जिले के विभिन्न थानों में चोरी और डकैती का वान्टेड था, पिस्तौल लेकर पलसाणा के जोलवा और बगुमारा क्षेत्र में घुम रहा था. कोई अपराध करने की तैयारी कर रहा है। जिसके आधार पर पुलिस ने स्थल पर जाकर खबर के विवरण वाले व्यक्ति को देखा और उसे अपने साथ ले गई. पुलिस ने आरोपी के पास से एक बनावटी पिस्टल भी बरामद की है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादक: संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोन: 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)